laln esa cgl % vke ctV 2013&14

'वाशिंगटन कांसेंसस' के बजाए 'दिल्ली कांसेंसस' बनाएं

ykd lHkk

- Mk- eqjyh euksgj tks'kh
- lqfe=k egktu
- gqDeso ukjk;.k ;kno

jkT; lHkk

- M. Venkaiah Naidu

Hkkjrh; turk ikVh

BHARATIYA JANATA PARTY

प्रकाशकीय

कांग्रेसनीत संप्रग सरकार का वर्ष 2013–14 का आम बजट संसद में पेश किया गया। हालांकि इस सरकार से कोई उम्मीद न होते हुए भी देश आदतन बजट की ओर टकटकी लगाए देखता रहता है कि शायद कुछ अच्छा हो जाए, पर मन ही मन में यह बात घर कर चुकी है कि इस सरकार के रहते देश के भले की उम्मीद करना बेमानी है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। इधर वित्तमंत्री श्री पी. चिदंबरम ने संसद में बजट प्रस्तुत किया उधर पूरी अर्थव्यवस्था को मानो सांप सूंघ गया, सेंसेक्स तो नीचे लुढ़का ही, पूरे देश का आत्मविश्वास डोल गया। ऐसे समय में जबकि देश की अर्थव्यवस्था के सारे सूचकांक औंधे मुंह नीचे गिर रहे हैं, बजट से कुछ ठोस पहल किये जा सकते थे। देश के उद्योगजगत, विश्व बाजारे, इस देश के युवा, किसान, गरीब, महिला और वंचित वर्गों को यह बजट कोई संदेश नहीं दे पाई। वस्तुतः यह बजट पूरी तरह कांग्रेसनीत संप्रग सरकार की कार्यप्रणाली को प्रतिबिम्बित करता है। जो 'पॉलिसी पैरालिसिस' और भ्रष्टाचार से ग्रसित है इस बजट से एक बार फिर निराशा का माहौल बना है जिससे अब लगता है कि यह सरकार जाते–जाते इस देश को उबार नहीं पायेगी।

कांग्रेसनीत संप्रग सरकार के पास देश को देने के लिए हताशा, निराशा, भ्रष्टाचार और कुशासन के सिवा कुछ भी नहीं है। संसद में बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी ने जहां बजट में भारत केंद्रित आर्थिक नीति के संदर्भ में कई प्रश्न खड़े किए, श्रीमती सुमित्रा महाजन ने 'जेंडर बजटिंग' एवं महिला सशक्तिकरण का विषय उठाया एवं श्री हुक्मदेव नारायण यादव ने गांव, गरीब एवं किसान का मसला सामने रखा वहीं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्री एम. वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में इसे गरीबों के लिए थोथे वादे एवं अमीर समर्थक बजट बताया। हम इस पुस्तिका में इन भाषणों का संपादित पाठ प्रकाशित कर रहे हैं। आशा है हमारे सुधी पाठक इससे लाभान्वित होंगे।

&Mk- f'ko 'kfDr cDlh

ebZ 2013

Hkkjrh; turk ikVh]

11] v'kksd jksM] ubZ fnYyh&110001

'वाशिंगटन कांसेंसस' के बजाए 'दिल्ली कांसेंसस' बनाएं

Mk- ejyh eukgj tk'kh

सभापति महोदय, वर्ष 2013–14 के सामान्य बजट के संबंध में आपने मुझे चर्चा करने के लिए समय दिया है। सबसे पहले मैं वित्त मंत्री महोदय के साहस को दाद देना चाहता हूं। उन्होंने ऐसे समय में वित्त मंत्री बनना स्वीकार किया, जबकि उनकी सरकार ने पिछले आठ–नौ सालों में अर्थव्यवस्था को बिल्कुल 1990 और 1991 की स्थिति में पहुंचा दिया। स्वयं प्रधान मंत्री जी ने यह कहा है कि अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है और हम वर्ष 1990 और 91 की तरफ जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि उन्होंने इस कार्य को, इस दायित्व को जब स्वीकार किया, तो चुनौतियों और समस्याओं की पूरी गंभीरता को समझकर किया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। ऐसी स्थिति में उनका जो बजट भाषण था, उसमें वह साहस या उनके अंदर की ऊर्जा मुझे दिखाई नहीं दी, जो ऐसी स्थिति में किसी वित्त मंत्री के भाषण में होनी चाहिए। इसमें परिस्थिति का वर्णन है। अगर इजाजत दें तो कहें कि परिस्थितियों का रोना है कि हाय, यह हो गया, हमारा एक्सपोर्ट गड़बड़ा गया, हमारे यहां बजट का घाटा बढ़ता चला गया, करंट अकाउंट डेफीसिट बहुत बढ़ गया। दुनिया में जो कुछ आर्थिक दृष्टि से कठिनाइयां आयी थीं, ग्लोबल मेल्टडाउन हुआ था, उसका हम पर प्रभाव पड़ गया। लेकिन हम उठ खड़े हो गये। यह बात तो ठीक है कि उठकर तो खड़ा होना ही है और मैं

आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि भारत उठ खड़ा होगा, इसकी आर्थिक स्थिति उठ खड़ी होगी, लेकिन तब उस तरफ हम होंगे और इस तरफ आप। उस स्थिति को उठाना तो है, वह तो भारत की जनता इस स्थिति को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी जो आज है। मैं कुछ आपके प्रस्तावों पर, हो सकता है कि कुछ तीखी आलोचना करूं।

आप तिरूक्कुरल के बहुत प्रशंसक हैं। उसका अक्सर आप उल्लेख करते हैं। मैं वैसे तो तमिल भाषी नहीं हूं। लेकिन मैं तिरुक्कुरल के एक बहुत अच्छे पवित्र वाक्य को बोलने की कोशिश करता हूं।

"Cevikaippachch sorporukkum panbudai vaendhan
Kavikaik keelthangum ulahu"

इसका अंग्रेजी भाषांतर है– "A ruler of quality,who accept swell-meant, though bitter criticism with patience and forbearance,will find all the wise support for him." मैं आशा करता हूं कि आप बहुत धैर्य के साथ उन बातों को सुनेंगे और उसमें से जो भी आपको वाइज़ सजेशंस लगें, उन्हें आप स्वीकार भी करेंगे क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था बिगड़ गयी और इसी हालत में चलती रही, तो यह कहने से काम नहीं चलेगा कि वित्त मंत्री आप थे। उसका नुकसान तो हम सबको उठाना पड़ रहा है। इसलिए मेरी आपसे बहुत विनम्र प्रार्थना है कि इस मामले को आप बड़ी गंभीरता से लें। यदि आप इजाजत दें, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप जिन सूत्रों का, जिन सिद्धांतों का अभी तक पालन करते रहे हैं, वाशिंगटन कांसेंसस के जिन सूत्रों को आप यहाँ लागू करते रहे हैं, अच्छा होगा कि आप बजाय वाशिंगटन कांसेंसस के दिल्ली कांसेंसस बनाएं, भारत के लोगों के साथ आमसहमति बनाएं, भारत की सभी पार्टियों के साथ आमसहमति बनाएं, भारत की गरीब जनता के साथ आमसहमति बनाएं, यहां के किसानों से, मज़दूरों से, आदिवासियों से, गरीब नौज़वानों से, मध्य–वित्त परिवारों से आमसहमति बनाएं। यदि ऐसी कोई दिल्ली कांसेंसस आप बनाएंगे, तो मैं समझता हूं आप एक अच्छी दिशा में देश की अर्थव्यवस्था को ले जाने के लिए याद किए जाएंगे। मगर यह मेरी सदिच्छा ही हो सकती है। मेरा आज तक का तजुर्बा यह है कि किसी अच्छी बात पर आमसहमति बनाने के लिए आप लोग नहीं तैयार होते हैं। यह आपकी इच्छा है, आपका अपना विचार है। लेकिन, जब भी मुझे सभापति महोदय ने बोलने का अवसर दिया है, मैं बार–बार आर्थिक मामलों के बारे में कहता रहा हूं कि यह केवल एक

पार्टी का मामला नहीं है, यह सारे देश का सवाल है। एक सौ बीस करोड़ से अधिक लोगों के जीवन का सवाल है। हमारे–आपके जीवन से ज्यादा हमारे देश की आने वाली पीढ़ी के जीवन का सवाल है। उन छोटे दूधमुंहे नन्हें बच्चों के जीवन का सवाल है, जिनके पास आज पढ़ाई की सुविधा नहीं है, दवाई की सुविधा नहीं है। इसलिए इसे आप एक महत्त्वपूर्ण विषय मानकर, मैं समझता हूँ, आगे विचार करेंगे। आप कहते हैं कि हमारा लक्ष्य है, 'Higher growth leading to inclusive and sustainable development'. इसे आपने मूल मंत्र बनाया है। अर्थात् आप कहते हैं कि ग्रोथ–इन–इक्विटी। ये आपका मूल मंत्र है। ग्रोथ का मतलब क्या? आपने आगे स्टिग्लिट्ज़ का एक उद्धरण दिया है। मैं भी उनका उद्धरण दूँगा, पर मैं आपसे निवेदन करूँगा कि क्या आपने स्टिग्लिट्ज़, अमर्त्यसेन और फितुशी की रिपोर्ट को पढ़ा। जब यूरोप में मेल्टडाउन हुआ, तब फ्रांस के उस समय के राष्ट्राध्यक्ष सरकोज़ी को यह समझ में आया कि हो क्या रहा है? प्रगति–प्रगति, ग्रोथ–ग्रोथ। लेकिन, यहाँ तो दुनिया बिगड़ रही है, उलट गया है मामला। There is no well-being; there is growth, but there is no well-being. तो उन्होंने एक कमीशन बनाया, जिसके सदस्य थे अमर्त्यसेन, जो एशिया और गरीब देशों की अर्थव्यवस्था के बहुत ही गहराई से जानने वाले अर्थशास्त्री थे, उसमें थे स्टिग्लिट्ज़, जिनका आपने उद्धरण दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के नोबल पुरस्कार प्राप्त थे। उसमें दो व्यक्ति नोबल लॉरिएट थे और तीसरे फितुशी थे, जो यूरोपियन अर्थव्यवस्था के बहुत ही प्रकाण्ड विद्वान थे। ये बहुत ही ग्लोबल स्तर के व्यक्ति थे, उन्हें भी कभी भी नोबल पुरस्कार मिल सकता है। उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी। उस रिपोर्ट की एक एक्जिक्यूटिव समरी भी है, रिपोर्ट बहुत बड़ी है। उस समरी का नाम है– "Mis-measurement of our lives -why the GDP does not grow". हमारे जीवन की समस्त आर्थिक गतिविधियों का ठीक ढंग से मापन नहीं हो रहा है। The basic question is about the mutualogy in economics - indicators, the parameters and particularly the GDP.

क्या जीडीपी का बढ़ ज़ाना, यह वास्तव में लोगों के जीवन स्तर को सुधरा हुआ बताता है? क्या जीवन स्तर की जो वास्तविकताएं हैं, वे सब जीडीपी में प्रतिबिम्बित होती हैं? यह केवल एक इंडैक्स हो सकता है, लेकिन समग्र जीवन को जिसे आप कहते हैं, inclusive and sustainable

development. उसका इसमें कहीं जिक्र नहीं होता है। इसलिए आपका आग्रह है जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने पर, ग्रोथ बढ़ाने पर, क्योंकि मैंने आपके बजट को पढ़ा। इसमें ग्रोथ के साथ–साथ आपका अर्थ केवल जीडीपी निकलता है। जीडीपी के अलावा भी कोई ग्रोथ का इंडिकेटर है, मॉनिटर है, उसका इसमें कहीं उल्लेख नहीं है। मैं चाहूंगा कि इस बारे में देश में गम्भीरता से बहस होनी चाहिए। दुनिया में हो रही है, हमारे देश में भी होनी चाहिए कि क्या वास्तव में जनता की आर्थिक, भौतिक उन्नति का एकमात्र पैरामीटर, एकमात्र इंडिकेटर, एकमात्र सूचकांक केवल सकल घरेलू उत्पाद है। क्या यह सारे जीवन को प्रतिबिम्बित करता है? क्या इसके अलावा और चीजें नहीं हैं? इसलिए जब आप कहते हैं हायर ग्रोथ, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ तो कैंसर में भी होती है, बड़े–बड़े ट्यूमर्स होते हैं। थायरायड में भी ग्रोथ होती है। फिर उसे आप कहें कि उस ग्रोथ को अब इक्वीटेबल में बांट दिया जाए, क्या यह सम्भव है, क्या उसका मतलब है। ग्रोथ का मतलब क्या है? Is it growth without jobs, growth without health, growth without education, growth without any other element of security; physical or otherwise. उसका मतलब क्या है? Happiness, contentment, pleasure, leisure, यह सब कहीं जीडीपी में रिफलेक्ट नहीं होता। लेकिन मानव जीवन के विकास के लिए जीडीपी ही कोई बात नहीं होता। ग्रोथ, समूचे समाज की ग्रोथ, सभ्यता की ग्रोथ, संस्कृति की ग्रोथ, जब तक ग्रोथ आल इंक्लुसिव नहीं होगी, जब तक ग्रोथ के अंदर जीवन के उत्थान के जितने भी सूचकांक सम्मिलत नहीं होंगे, तब तक ग्रोथ केवल हवा में या अंधकार में सीटी बजाने की तरह है। इसका कोई यथार्थ, भौतिक मतलब नहीं होगा। यह केवल एक आंकड़ों का भ्रमजाल है। आप देखेंगे कि उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि मनुष्य की उन्नति, समाज की उन्नति, विश्व की उन्नति जानने के लिए कितने जटिल प्रकार के पैरामीटर नापने होंगे और उसकी तरफ विश्व को बढ़ना चाहिए। अगर सही मायनो में आप कोई अर्थ सुधार करना चाहते हैं। लेकिन आप तो वाशिंगटन कांसेंसेज से बंधे हुए हैं। उससे एक इंच इधर भी नहीं जाएंगे, एक इंच उधर भी नहीं जाएंगे। उनका मूल मंत्र है वह कर दो –निजीकरण, उदारीकरण और वैश्विकरण, सीधी सी बात है। लेकिन वही स्टिग्लिट्ज़, जिसको आपने उद्धृत किया है, वह क्या कहते हैं, उन्हें जरा देखिए।

"Globalization, like development, is not inevitable even though there are strong underlying political and economic forces behind it. By most measures, between world war-I and world war-II both the paceand extent of globalization slowed and even reversed. For example, measures of trade as a percentage of GDP actually declined. If globalization leads to lower standards of living for many or most of the citizens of the country and if it compromises fundamental cultural values then there will be political demands to slow or stop. "

I do not find, Mr. Finance Minister,any reference to the culture or values in your entire Budget statement. It is devoid of culture. It is devoid of values. It is onlya hollow statement, a hollow balancing of the incomeand expenditure of the Government which any Chartered Accountant can do. And, therefore, my most humble suggestion to you is, please rise from the role of the Chartered Accountant and try to become the Finance Minister because Budget is nothing. आपने क्या किया है, मैं उस बारे में भी आपसे आगे चर्चा करूंगा। स्टिग्लिट्ज़ और भी आगे कुछ कहते हैं। आप तो फ्री मार्केट और केपिटलिज्म के पुरोधा हैं और स्टिग्लिट्ज़ को कोट कर रहे हैं। स्टिग्लिट्ज़ कहते हैं,

"There is also a growing recognition that there is not just one form of capitalism, not just one right way of running the economy. Thereare for instance, other forms of market economy such as that of Sweden which has sustained robust growth that had led to quite different societies marked with better health careand education and less inequality. While Sweden's version may not work as well else where or may not be appropriate for a particular developing

country, itssuccess demonstrates that there are alternative forms of protective market economy."

I was happy when the Chinese leaders came and told your Party also to not follow the Chinese system and develop an Indian system. So that is the way. Stiglitz says that there is no hard orset or one rule which is applicable to the whole of world. That is the real mistake which you are committing in this country.

प्लानिंग कमीशन से एक सेट बनाया और सारे देश पर लागू कर दिया। राजस्थान में भी वही लागू करिये, कश्मीर में भी वही लागू करिये, सुंदरबन में भी वही लागू करिये और केरल में भी वही लागू करिये, इस तरह से नहीं चलता है।

Therefore, the whole system has to be reviewed, rechecked and reframed. Perhaps, you will not get the opportunity to do that. That may perhaps come on the shoulders of some persons sitting on this side.

Then he says:

"When there are alternatives and choices, democratic/ political process should beat the centre of decision making and not bureaucratic centric. One of my criticisms - that is of Stiglitz criticism - of the international economic in stitutions is that they try to pretend that there are no trade offs. A single set of policies made everyone better off while the essence of economics is choice that the reare alternatives some of which benefit some groups such as foreign capitalists at the expense of others, some of which impose risks on some groups such as workers and labourers to the advantage of others."

इसलिए जब आप उद्धरण दे रहे हैं तो उसके पूरे सिद्धांत को सामने रखकर उद्धरण दीजिए, केवल उसके एक वाक्य को वनज वबिवदजमगज लेकर बात नहीं बनेगी। वह आगे कहते हैं–

"Those who are less concerned about inequality and

more concerned about economic efficiency, tend to be less concerned with noneconomic values such as social justice, the environment, cultural diversity, universal access to health careand consumer protection."

अर्थात अगर आपको विकास करना है तो घिसे–पिटे मॉडल पर जिसे आप बेटन–रूल–इंस्टीट्यूशन्स कहें, वाशिंगटन कंसेंसस कहें, जी–20 फॉर्मूला कहें, जी–8 फॉर्मूला कहें, जो कुछ आप कहें, उससे काम नहीं चलेगा। एक नयी चीज की जरुरत है, एक नयी सोच की जरुरत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आपने इस अखाड़े में कदम रखा है तो सोच कर चलिये कि पुराने जितने भी सोल्यूशन्स हैं वे काम नहीं आयेंगे, नयी बात लानी पड़ेगी क्योंकि नयी परिस्थिति है। देश के सामने नयी चुनौतियां हैं, आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। आप नयी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, सोचने के लिए तैयार नहीं हैं, आप केवल माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अध्यक्षा यूपीए के अलावा कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं हैं। देश में और भी कुछ है, उसके आगे भी बहुत कुछ है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, जहां उस तरफ ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपने फंडामेंटल्स को ठीक करने की कोशिश करें। अगर उन्हें ठीक नहीं करेंगे तो यह स्थिति निश्चित रूप से वर्ष 1990–91 तक पहुंच कर ही रहेगी, उससे पहले रुकेगी नहीं।

आपका इसमें हमारे लिए एक और महत्वपूर्ण संदेश है। Stiglitz ने जो मोरल केस फॉर इक्विटी कहा है और आप कहते हैं कि

> "We have examples of States growing at a fast rate but leaving behind women, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the minorities and some backward classes."

This is precisely your model. You have left behind Scheduled Castes, adivasies, un organized sector and you have left behind the vast number of unemployed young men. यह तो आपका मॉडल है, आप इसे रिजैक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप खुलकर कहिये कि यह हमसे गलत हो गया, हमसे गलती हो गयी। आइये, फिर आपसे बात करें। हिंदुस्तान में इसके अलावा ऐसे भी मॉडल्स हैं जहां हर गरीब आदमी का ख्याल किया गया है, जहां आदमी ही नहीं, आदमी के साथ काम करने वाले जानवरों का भी ख्याल किया गया है,

गाय–भैंस–बैल का भी ख्याल किया गया है, यहां मुर्गी और मुर्गी के बच्चों का भी ख्याल किया गया है। जहां गरीब आदमी का भी खयाल किया गया है। जहां एग्रीकल्चरल ग्रोथ 18 परसेंट तक हुई है। ऐसे कई माडल्स हैं। आप उनकी तरफ देखिए। ऐसे माडल्स भी हैं जहां एक रुपए में चावल देने की बात है, जहां पांच रुपए में भरपेट भोजन देने की बात हो रही है। मेरा निवेदन है कि आप छत्तीसगढ चलिए, वहां पांच रुपए में भरपेट भोजन रिक्शे वालों के साथ, टांगे वालों के साथ तथा दूसरे गरीब लोगों के साथ कीजिए। दाल, चावल, सब्जी वगैरह आपको मिलेगी, तो आप क्यों नहीं दे सकते हैं। चूंकि वाशिंगटन कांसेंसिस में वह माडल नहीं आता, उसमें गरीब आदमी के साथ बैठकर खाने का जिक्र नहीं होता, इसलिए आप उसे नहीं मानेंगे। यही आपका संत्रास है, यही आपकी त्रासदी है। आपने बहुत अच्छी बात कही – The purpose of a Budget and the job of the Finance Ministerare to create economic space and find resources to achieve the socio-economic objectives. यह सही बात है। यह फाइनेंस मिनिस्टर का काम है लेकिन आप देखें कि इकोनोमिक स्पेस कहां से पैदा करें, कैसे पैदा करें और रिसोर्सेस कहां से आएं। इसके लिए मेरा पहला अनुरोध है कि आप सबसे पहले भारत को समझ लें। भारत का आर्थिक स्पेस कहां तक फैला हुआ है और आज कहां है, पहले इसे जानिए तभी आगे का स्पेस होगा। आपने एक बार विदेश में अंग्रेजों को और अमेरिकंस को भाषण दिया था कि आप भारत आए थे और दो सौ साल तक रहे। खूब समृद्ध हो कर गए। आप फिर से आइए, रहिए और आपको बहुत लाभ होगा, बहुत मुनाफा होगा। आपने अभी तक इसका खंडन नहीं किया है, अगर आप इसका खंडन कर देंगे, तो खुशी होगी। आपने यह कहा, इसका मतलब है कि आपको अंग्रेजों के आने से पहले के भारत के स्पेस का पता ही नहीं था। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कम्पनी जब 1600 में आई, तब भारत का इकोनोमिक स्पेस 24 परसेंट आफ दि वर्ल्ड जीडीपी था। जब अंग्रेज यहां से दो सौ साल बाद गए, तब तीन परसेंट के करीब जीडीपी थी और आज साठ–पैंसठ साल के बाद उतनी भी जीडीपी नहीं है। आप हर साल कहते हैं कि दुगुना करेंगे, हर प्लान में कहते हैं कि दुगुना करेंगे लेकिन पौने दो परसेंट, दो परसेंट, सवा दो परसेंट ही है। आप कौन–सा इकोनोमिक स्पेस पैदा करना चाहते हैं? इकोनोमिक्स तो काफी लचीली होती है। इसमें तो बहुत इलास्टिसिटी है। आप कितना बड़ा स्पेस कर सकते हैं? क्या आप

चौबीस परसेंट कर सकते हैं, तब तो आप 16वीं सदी के स्पेस में पहुंचेंगे। क्या आप किसी ऐसी इकोनोमिक स्पेस की कल्पना कर सकते हैं। देश के वित्त मंत्री के नाते यह कल्पना करनी चाहिए कि 16वीं सदी में हमारा जो स्पेस था, वह 2012, 2014, 2015, 2016, 2020 में सवा या डेढ गुना ज्यादा स्पेस लेने की हमें हिम्मत करनी चाहिए, लेकिन आप तो वहीं घूम रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आप भारत की अर्थव्यवस्था को क्या दिशा देना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि थोड़ी–बहुत लंगड़ी दौड़ चलती रहे कि कभी आधा परसेंट बढ गई, कभी पौन परसेंट बढ गई, कभी टैक्स इधर बढ़ा दिया, कभी टैक्स उधर घटा दिया। आप वित्त मंत्री की तरह काम कीजिए। देश को वित्त व्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की, रिसोर्स की, मोबेलाइजेशन की ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश कीजिए। मैं उस भंडार की बात नहीं कहना चाहता हूं जो उन्होंने हमारे यहां से लूटा व्यापार के तौर पर भी और हम लोगों के तौर पर भी, मैं नहीं समझता कि आज कोई भी वित्त मंत्री यह कह सकता है कि वह कोहिनूर हीरा जो हमारे यहां से गया था, अगर वह हीरा चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे बड़ा हीरा हम देश में ला कर दिखाएंगे। ऐसा कोई नहीं कहता है। उसे लाने का विचार छोड़ दिया है, उसे मना कर दिया है। लेकिन उससे बड़ी चीज ला कर दिखानी चाहिए। तख्ते ताऊस चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन हम कुछ और बना कर दिखाएंगे। उससे बड़ा तख्त बना कर दिखाएंगे। देश में बड़ी समृद्धि ला कर दिखाएंगे। ऐसा नहीं कहा है। डेढ़ परसेंट, दो परसेंट, सवा दो परसेंट, क्या यह कोई देश है? एक अरब बीस करोड़ लोगों का देश, सारी समृद्धि से भरा हुआ, सारे टेलेंट से भरा हुआ देश, सारे पुरुषार्थ और ऊर्जा से भरा हुआ देश है, लेकिन आप उसे केवल सवा परसेंट, दो परसेंट पर नचा रहे हैं। आप वर्ष 1990–91 की तरफ देश को वापिस ले जा रहे हैं। यह कैसा बजट है, कैसी वित्त व्यवस्था है, कैसा चिंतन है, मुझे बहुत अफसोस है।

फिर आपने कहा कि क्या करें? बड़ी तकलीफ है। मगर फिसकल डैफिसिट, करेंट एकाउंट डैफिसिट और इंफ्लेशन ये हमारे लिए बड़ी समस्याएं हैं लेकिन अब आप इनका निदान क्या करते हैं? आप कहते हैं कि फॉरेन इंवेस्टमेंट, एफडीआई, एफआईआई और एक्सटर्नल कॉमर्शियल है और आपका एक वाक्य देखकर मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि आपने यह कैसे कहा है कि आप बार बार इसके लिए आग्रह करते आ रहे हैं।

"At present, the economic space is constrained

because of the high fiscal deficit, reliance on foreign inflows to finance the current account deficit, lower savings and lower investments, etc. During the course of my speech, I shall spell out measures that will address each of these issues."

अब इसमें आपने करेंट एकाउंट डैफिसिट के लिए जो सबसे ज्यादा आग्रह किया है, वह यही कहा है कि "If I may be frank, foreign investment is an imperative. What we can do is to encourage foreign investment that is consistent with our economic objectives?"

What are your economic objectives? No where you have spelt out the economic objectives in this Budget. Is it only to help certain growing industries and industrialists in this country? Or is it to help the poor, the destitute, the deprived, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, the backward classes and the most backward classes?what is your objective? Do you want to create an egalitarian society or create a capitalist society? आप क्या चाहते हैं? आपका क्या उद्देश्य है? इसलिए मैंने कहा कि इस पर बहस होनी चाहिए। what are your objectives? There should be a consensus on the economic objectives of the nation. There cannot be economic objectives of one Party or two Parties or three Parties. There has to be a national consensus on economic objectives and that cannot be only to marchat 1.8 per cent or 1.75 per cent of the world space in economics. It should be to cross that 24 per cent. It should that there will be no-body hungry in this country. कोई आदमी बिना गेनफुल और डीसेंट एम्पलॉयमेंट के नहीं रहेगा। आपने इसमें कहीं नहीं लिखा है। आपके क्या उद्देश्य हैं? शब्दाडम्बर कह दीजिए। Goals must be concrete. समय तय करिए। आप उधर हैं। मैंने बार बार कहा है कि अगर देश के लिए सांझा कोई कॉमन कंसेंसस बनता है, सारे देश के सम्पूर्ण विकास के लिए अगर सर्वसहमति बनती है जिसमें कल्चर वगैरह सब शामिल है तो मैं समझता हूं

कि आप उसमें देश को आगे ले जा सकेंगे। मगर अफसोस, आप सिर्फ कदमताल करना चाहते हैं, आगे बढने़ की स्थिति नहीं है। अब आप कहते हैं कि यही सबसे जरूरी है तो यही होगा। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था। अभी एक बात और बता देता हूं जो उन्होंने कहा। आपको काफी पसन्द है। उन्होंने एक बात और कही है। Joseph Stiglitz states:

"Why should you import the wal-mart culture? Not only wal-mart as a shop but walmart as a culture." It is the economic culture which the wal-mart is propagating. It is the culture which flows from the economic system. It is the culture of exploitation, the culture of high profit and this is a culture which is completely de culturalised. There is no human culture in it. There is no human value in it. This culture is only profit and exploitation. So,wal-mart is not only a shop but wal-mart is a culture. "India is famous for being the land with the high per capita of billionaires. This is striking for an average country with so many people. There is that huge divide now from the very top that is no longer class based but money based in redefining of divisions within the society. We have changed the rules of the game to give more weight to moneyed interests just at the time when inequality is growing. US firm is planning to set up nuclear plants should bear all the liability but they do not do that even in the US, state subsidies protect them. India has a large talented entrepreneurial class, and lots of savings and wealth. Why should it need foreign entrepreneurs in any sector?"

And if you start taking foreign entrepreneurs in economic sector beyond a limit, the daysare not far away when this whole Parliament House will be governed by

certain foreign interests, if not foreign people.

यह मत कीजिए। सोच समझकर कीजिए। इसे मात्र इम्पेरेटिव मत मानिए, जितनी जरूरत हो लीजिए। दवाई की जितनी जरूरत हो जरूर लीजिए लेकिन बॉडी की इम्युनिटी ज्यादा जरूरी है। शरीर में प्रतिरोधक क्षमता होना ज्यादा जरूरी है। एक आदमी जो कैंसर से ग्रस्त है, उसे थोड़ी देर जिंदा रखा जा सकता है लेकिन उद्धार नहीं किया जा सकता है।

Finally, the developments must be sustainable, economically and ecologically. इसमें कहां बैलेंस है? एक मिनिस्टर कुछ कह रहा है आप कुछ कह रहे हैं। अभी मिनिस्टर ने फरमाया कि इथिकल मार्किट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो मार्किट आप डील कर रहे हैं वह अनइथिकल है। अखबारों में बड़ी हेडलाइन है। इकोलाजी वाला कुछ कह रहा है और इकॉनामी वाला कुछ कह रहा है। इसमें तमाशा यह है कि दोनों ईको से संबंधित हैं। One is the knowledge of eco and the other is the management of eco, but both are at logger heads. इकोलाजी कुछ और कह रही है, इकॉनामी कुछ और कह रही है। आपकी तो सारी सरकार में ही झंझट है, उसके बारे में मैं बाद में कहूंगा।

महोदय, मेरी समझ में नहीं आता है इसमें आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रियारिटी क्या है? कितना डेवलपमेंट है? अभी माननीय गृह मंत्री जी कह रहे थे कि आदिवासियों के साथ झारखंड ने बहुत अन्याय किया है। हो सकता है हो रहा हो। कहां नहीं हो रहा है? सारा डेवलपमेंट प्लान आदिवासियों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, बेसहारा लोगों के खिलाफ है। स्टडीज तो यह कह रही हैं कि बहुत सा अनरैस्ट इस देश में इसलिए हैं क्योंकि आपका प्लान लोगों के जीवन को डिस्टर्ब कर देता है। Mr. Joseph Stiglitz says: If it compromises fundamental cultural values, then there will be political demands to slow or stop it." रीड पोलिटिकल अनरैस्ट, रीड इकनॉमिक अनरैस्ट। वित्त मंत्री जी आपने चुनौती स्वीकार की है लेकिन आपके पास हथियार नहीं हैं। आपके साथी आपका साथ नहीं दे रहे हैं।

आपने पहले ही कहा है कि इन्फलेशन बहुत है। क्यों है? अनाज के भंडार भरे हुए हैं तो फूड इन्फलेशन क्यों है? लाखों टन अनाज के भंडार है, जितना बफर रिजर्व चाहिए उससे ढाई–तीन गुना आपके पास है। नई फसल

आ जाएगी तो आपके पास रखने की जगह नहीं होगी। हां, आप जान बूझकर सड़वाते हैं और फिर शराब बनाने वालों को बेच देते हैं। क्या फायदा? आप गरीब आदमी को दीजिए। हमने मुफ्त में दिया है। दिया जा सकता है। भूख मिटाइए। भूख बड़ी जबरदस्त चीज होती है। कुछ दिन भूखे रहकर देखिए तब पता चलेगा कि भूख के क्या मायने होते हैं। उपनिषद् में एक कहानी है, एक लड़के ने कहा कि मैंने ब्रह्म को समझ लिया है। पिता ने कहा – बेटा तीन दिन बाद भूखे रहकर आना। तीन दिन बाद बेटा भूखा रहकर पहुंचा तो पिता ने कहा– बेटा, ब्रह्म क्या है? तब बेटे ने कहा – पहले अन्न चाहिए, ब्रह्म तो बाद में देखूंगा। अन्नः ब्रह्मः। आप उस ब्रह्म को सड़वा देंगे? क्या कर रहे हैं? where is the cultural value? इकॉनामी किधर जा रही है। एक तरफ किसान मर रहा है, दूसरी तरफ अनाज सड़ रहा है और तीसरी तरफ आदमी भूखा मर रहा है। हम यहां बैठकर बहस कर रहे हैं? बजट हो रहा है। अजीब हालत है? किस बात का बजट हो रहा है? किसके लिए हो रहा है? किस मामले में हो रहा है? आप सिर्फ लेखाजोखा बराबर कर रहे हैं और क्या हो रहा है? This is not the way. यह ठीक नहीं है।

आपने कहा हमने राजकोषीय घाटा कम कर लिया, फिसकल डेफिसिट कम कर लिया, बजटरी डेफिसिटी कम कर लिया। कैसे कर लिया? बहुत तमाशा है। वही तो मैं कहता हूं कि चार्टिड एकाउंटेंट का काम है। पिछली बार आपने बजट में जो एस्टिमेट्स दिए थे, आपने देखा कि वह पूरे नहीं हो पाए इसलिए सब मिनिस्टरों से कहा कि घटाओ, घटाओ और घट गया। 60,000 करोड़ घटा दिया और फिर कहा, देखो 5.2 पर आ गए। आप इसमें 60,000 जोड़ दीजिए।

आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हिम्मत के साथ कहिये कि यह खर्च होना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा बढ ज़ाता है। दुनिया वाले और हम तो टोकेंगे, हमने यह वचन दिया है। अगर नहीं दे सकते तो कोई जरूरी नहीं है। अगर देश की जरूरत के लिए आपको 2–4 पाइंट बढ़ाना भी पड़ जाए तो कौन सी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, आम आदमी, देश की अर्थव्यवस्था, देश का जिंदा रहना, देश के उद्योग, देश का मजदूर या ये आंकड़ा कि हमने बजट डेफिसिट कम कर दिया। हमने क्या किया, हमने बड़ी कुशलता से देश की अर्थव्यवस्था को मैनेज किया। लोग भूखे मर रहे हैं, मरने दो, लेकिन हमारा बजट घाटा 5.2 आ गया। मेरी समझ में नही आता कि यह कौन की अर्थव्यवस्था है। आदमी महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण है या यह आंकड़ा

महत्वपूर्ण है, कुछ समझ में नहीं आता। जब मैं इसे पढता हूं तो मुझे हंसी आती है। कहीं आप कहते हैं कि बजट ऐस्टीमेट की तुलना में इतना है और कहीं कहते हैं कि रिवाइज्ड ऐस्टीमेट की तुलना में इतना है। आप पिछले बजट ऐस्टीमेट से अपना बजट ऐस्टीमेट कम्पेयर कीजिए। पिछले रिवाइज्ड़ ऐस्टीमेंट से अपना रिवाइज्ड ऐस्टीमेट कवर कीजिए। लेकिन आप ये ऑरेंज और एपल्स क्यों कम्पेयर कर रहे हैं? कहीं आपको दिखाई देता है कि बीई की तुलना में हमने बढ़ा दिया, कहीं आप कहते हैं कि हमने आरई की तुलना में बढ़ा दिया। आप इसे गौर से पढ़िये और इसकी गलतियां ठीक करिये। ऐसे कोई फायदा नहीं होता है। देश की जनता सब समझती है, वह इतनी बेवकूफ नहीं है कि इन बातों को न समझे। आप इसमें देख रहे हैं, आप कहते हैं, मैं एक उदाहरण देता हूं – "The Plan Expenditure in 2013-14 will be 29 per cent more than the Revised Estimates of the Current Year but it is only 6 per cent more than the Budget Estimate." लोगों ने सुन लिया, अखबार वालों ने छाप दिया, जनता प्रसन्न हो गई। लेकिन जब उसे इन विटविन दि लाइंस पढ़ा गया तो समझ आ गया। ऐसे बहुत से तमाशे हैं, यह कोई भी पढक़र देख सकता है। आप एक–एक मिनिस्ट्री का कम्पेरिजन कर लीजिए, आपको पता लग जायेगा कि कहां कितना घटाया है और जितना आपने यहां घटाया है, उतना ही आपका घाटा कम हुआ है और कुछ बातें हैं। So, this is the work of a Chartered Accountant- इसके लिए आप जैसे विद्वान आदमी की जरूरत कहां थी। ऐसे लोग तो आपके ऑफिस में काम करते हैं, जो ये काम कर सकते हैं। It is not needed. For this, a Finance Minister of your calibre is not needed.

इसके बाद आप कहते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और इन लोगों का आपने बहुत फेवर किया है। मैं आपको बता देता हूं कि क्या किया गया है और उसमें क्या हुआ है और कैसे–कैसे हुआ है। Money is spent but who are the beneficiaries? They are but for the fortunate ones. एससी एंड एसटी के जो आपके सब–प्लान हैं, उसमें प्लान में खर्चा तो है, लेकिन हुआ नहीं है। Scheduled Caste population share is 16.2 per cent; Scheduled Caste Sub-Plan is Rs.37,113 crore. For 2013-14, it is Rs.41,561 crore. बजट शेयर दोनों में 9.50 टू 9.9 है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी आपका वही शेयर 5.56 टू 5.87 है।

लेकिन यहां आप देखिये। For example, the seed infrastructure facility under the Ministry of Agriculture has set aside Rs.79 crore to Scheduled Caste Special Plan and Tribal Special Plan. While the National Food Security Mission has set aside Rs.270 crore for it, the NFSM is about raising of crop yields. There is no scheme for helping Scheduled Caste/Scheduled Tribe people. किस एससी एंड एसटी की मदद हो रही है। For the Scheduled Caste/Scheduled Tribe people, is that theway of your investment, is that theway of your allocation? मेरे पास बहुत से आंकड़े हैं, लेकिन भाषण बहुत लम्बा हो जायेगा, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं।

आप सर्व शिक्षा अभियान को लीजिए। A sum of Rs.4,793 crore is for Scheduled Caste and Scheduled Tribe people and TSP but there are no schemes specific to the admission of Scheduled Caste or Scheduled Tribe children or recruitment of Scheduled caste and Scheduled Tribe teachers. Again, a sum of Rs.2,284 crore is set aside under the head of the Midday Meals Scheme though this is meant for all children- वह तो सबको वैसे ही है। आपकी मिनिस्ट्री का क्या हिसाब है कि रुपया रखना है, रख दो, खर्च नहीं होना, डाल देंगे घाटा बच जायेगा। प्लीज, ऐसे बजट को मत बनाइये। यह बड़े अफसोस की बात है, हिदुस्तान के लोगों को इससे बहुत तकलीफ होती है।

महोदय, मेरे पास बहुत से आंकड़े हैं। हैल्थ को लीजिए, हैल्थ में ब्रिक्स कंट्रीज में सबसे कम हैल्थ पर खर्चा हमने किया है। आपके पास मेरे से भी ज्यादा आंकड़े होंगे। लेकिन आप देखिये, आपने आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के लिए कहा कि they are being main streamed through the National Health Mission.

Ayurveda is the mainstream medicine of this country! Unani is here forso many hundreds of years. जब से हमारा अरब से कॉन्टेक्ट है, तब से यूनानी सिस्टम है। जब से होम्योपैथी से आई है, वह तब से हमारे देश के अंदर है। सिद्धा तो पैदा ही हमारे देश में हुआ है। आप यह कहिए कि इनकी स्ट्रीम सूख रही थी, उसको रीचार्ज कर रहे

हैं, एनरजाइज़ कर रहे हैं। Do you mean to say modern medicine is the mainstream medicine of this country? This is a new stream - 300 years. अभी 60–70 साल पहले एलोपैथिक मैडिसिन में पांच–छह मिक्सचर्स के अलावा कुछ नहीं होता था। डॉक्टर साहब आते थे, बॉक्स में पांच–छह मिक्सचर रखते थे – मिक्सचर नंबर 1, मिक्सचर नंबर 5। It is a 300 year old good story, a successful story. But please don't confuse this country.

You call it a san emerging economy. What do you mean by 'emerging economy'? It had 24 per cent space in the year 1600 and now, in 2013, you say, 'emerging'. In fact, you have converted in to a submerging economy. How? आपकी सारी इकनॉमी ऋणग्रस्त है। It is completely under debt, losses?

Now look at telecom sector, financial loan Rs.2 lakh crore debt; this was September-October, 2012; banking sector -Non-Performing Assets - Rs.1.37 lakh croreas on June, 2012. Then, according to RBI's assessment, a fifth of all structured loans go back. According to RBI, as on March 31st, 2012, banks had Rs.2.18 lakh croreworth of restructured loans in its books and I don't think that any thing would be recoverable. Then, credit card out standing - Rs.22,150 crore. पता नहीं कि यह आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा?

Indian Government - total Plan borrowing is Rs.5.7 lakh crore, of which Rs.2 lakh crore would be in the second half of the fiscal. Then, banking sector - Report of Credit Suisse Group - 80 points that exposure to 10 large industrial groups constitute 13 per cent of the entire banking sector. Indian banks had loans outstanding worth Rs.3,36,600 crore to the mining sector; Rs.93,000 crore to the telecom sector, and power sector. The accumulated losses of the State power distribution companies are estimated to bealone Rs.1.90 lakh crore,which must have

crossed Rs.2 lakh crore. उसका इंट्रस्ट बढ रहा होगा।

Air India -anamount of loss is Rs.67,520 crore. This is the figure of February.

On account of Pantaloons, there isa loss of Rs.3,300 crore. If you add all the losses, then, you see the total loss comes to Rs.40,500 crore in the beginning of the year. वह बढ गया होगा। उसके साथ देखिए कि आप रिसोर्स कहां से पैदा करेंगे। आपने कहा है कि आपकी जो नॉमिनल ग्रोथ है, वह पिछले साल 12 प्रतिशत थी। उसके पहले जो आपकी एवरेज नॉमिनल ग्रोथ है, वह 15 प्रतिशत है। इस 15 प्रतिशत से 12 प्रतिशत होने में Output loss is Rs.3 lakh crore - just in one year, and we lost Rs.3 lakh crore. इस साल भी आप कह रहे हैं कि यही होगा। 12 प्रतिशत होगी या 13 प्रतिशत होगी। Another two lakh core. आपके जाने से पहले आप यह आउटपुट लॉस छोड़ कर जाएंगे तो फिर रिसोर्स कहां से लाएंगे? जो रिसोर्स आप बताते हैं, मैं बताऊंगा कि उसकी क्या हालत है। बैंकों की हालत यह है कि रियलिटी और सब को मिला कर 4 लाख 37 हज़ार करोड़ रूपये रियल इस्टेट में आपका एक्सपोज़र है। 5 लाख मकान ऐसे हैं, जो अभी तक टिके नहीं हैं।

कृषि – अब आप देखिए कि दुनिया भर में हालत खराब है। The US is facing a severe drought and India has witnessed a bad spell of monsoon this year with erratic and unpredictably low snowfall.

अभी तक आप यही कह रहे थे कि बहुत खराब फसल है, बहुत खराब फसल है, लेकिन स्टॉक पाइल्स ऑफ दि बिगेस्ट क्रॉप्स अभी तक हमारे यहां थे। आप बाहर से ऑयल सीड्स और पल्सेज मंगाते हैं, उन देशों में इस बार क्या हाल है, कुछ पता नहीं है।

"Combined inventories of corn,wheat,soya beans and rice will drop 1.8 per cent to a four year low before harvest in 2013."

यू.एस. गवर्नमेंट के यहां हालत खराब हो रही है क्योंकि यह कोर्न आदि सब उन्हीं के यहां का है।

"Wheat production in Russia, the fourth largest

exporter,will fall 20 per cent this year and in Australia, the output will decline 19 per cent and God forbid, another year of badspell of rain in India may also create more problems for us."

Under these conditions, how are you going to control the food inflation? अगर बाहर फूड नहीं हो रहा है, आपके यहां है तो आप या तो एक्सपोर्ट करोगे तो दाम बढ़ेगा और अगर बाहर फूड नहीं है, वहां के महंगे फूड को इम्पोर्ट करोगे तो दाम बढ़ेगा। Food is the major contributor to inflation. उसे आप कैसे कंट्रोल करोगे? आपने कहा कि हम कंट्रोल कर लेंगे। मैक्सिमम कान्ट्रीब्यूशन फूड का है। फूड आप देते नहीं, बाजार में खोलते नहीं, सेलोज बनाते नहीं, पता नहीं क्या करते हैं? हर साल कहते हैं कि सेलोज बनेंगे, लेकिन बनते कुछ नहीं। इसका नतीजा यह है कि जो एग्रीकल्चर हमको पहले 53 परसेंट कान्ट्रीब्यूट करती थी, वह अब 13–14 परसेंट कान्ट्रीब्यूट कर रही है। 60–65 परसेंट लोग इतना कम कान्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्यों नहीं आप एग्रीकल्चर से लोगों को कहीं ला सकते? जॉब्स कहां हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जॉब्स नहीं हैं, सिर्फ सर्विस सेक्टर में थोड़ी सी जॉब्स बढ़ी हैं। पिछले सालों का मेरे पास सारा आंकड़ा है कि कहां–कहां जॉब्स की क्या हालत है? आपने कहा था कि अगर हमारी 8 परसेंट ग्रोथ हो जायेगी तो हम एक करोड़ जॉब्स क्रिएट कर देंगे। 8 परसेंट ग्रोथ अगले साल कैसे होगी? अगर इटली के वोट का कोई नतीजा हमको यूरोप में दिखाई दे रहा है और यूरोपियन इकोनॉमी बिल्कुल वहीं कदमताल कर रही है या पीछे हट रही है तो यह आपकी ग्रोथ कहां से होगी? आपने अपने दूसरे मार्केट्स तो अभी डेवलप नहीं किये। सवाल यह है कि अगर एक्सपोर्ट आपका बढ़े नहीं, इंटरनल रिसोर्सेज आपके बढ़े नहीं, तो आप कहते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर लायेंगे और उससे बहुत पैसा करेंगे। यह बिल्कुल ठीक है, आपने इसमें कहा है, मैंने इसे देखा है, वह बहुत ही अच्छी बात है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कुछ कहा है, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एन इंडस्ट्री, आपने एक बात कही है कि आप 55 लाख करोड़ 12वें प्लॉन में इंफ्रास्ट्रक्चर में रखेंगे। यह इनका भाषण है:–

"The 12th Plan projects an investment of USD 1 trillion or Rs. 55,00,000 crore in infrastructure."

तो एक साल में 11 लाख करोड़ हुआ, ये 11 लाख करोड़ आप एक साल

में कहां से लायेंगे? आप कहते हैं कि 47 परसेंट इसमें प्राइवेट शेयर होगा और बाकी इसमें पब्लिक शेयर होगा। 47 परसेंट जो इसका है, वह 5 लाख 17 हजार करोड़ होगा, ये 5 लाख 17 हजार करोड़ आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक साल में कहां से लायेंगे? यानी वे प्राइवेट वाले कहां से लायेंगे, दुनिया से उधार मांगेंगे, क्या करेंगे? फिर आपने जो रास्ते बताये हैं, उसमें मैंने हिसाब लगाया, सिर्फ 75 हजार करोड़ पैदा होता है। फिर कहते हैं कि पब्लिक शेयर जो है, वह 5 लाख 83 हजार करोड़ है, यह पार्लियामेंट कहां से इम्पोर्ट करेगी 5 लाख 83 हजार करोड़। कहीं जिक्र नहीं है कि यह 5 लाख 83 हजार करोड़ कहां से आयेगा? आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड्स, जहां देखो कर्जा, जहां देखो कर्जा, विदेशों से बॉड लो, यह कर लो, वह कर लो, यानी अपने हाथ में आपने कुछ नहीं रखा, जो करना है, उनके भरोसे करना है, यह क्या है? मेरी समझ में नहीं आया कि आप 5 साल में 55 लाख करोड़, 1 साल में 11 लाख करोड़ और इसमें से 5 लाख 17 हजार प्राइवेट करेगा और 5 लाख 83 हजार पब्लिक सेक्टर करेगा। कोई रास्ता तो दिखता नहीं है। जो अर्थव्यवस्था की हालत है और जो दुनिया की हालत है, उससे तो कहीं हमको दिखता नहीं है। फिर आप रोड कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, रोड का क्या हाल है? मैंने देखा है कि आपने स्टेट्स को भी जो पैसे दिये हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में घटा दिये हैं।

रोड कंस्ट्रक्शन सबसे कम हुआ है। इनफ्रास्ट्रक्चर में आप क्या बनाएँगे – हवाई अड्डे या सड़क? इनफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ह्यूमन इनफ्रास्ट्रक्चर बनेगा या नहीं, साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा या नहीं? आपने कहा कुछ रुपये रखे हैं। उससे क्या बनने वाला है? कहीं फोकस करिए। इधर–उधर मत बाँटिये। हाँ, बाँटना आपकी मजबूरी है क्योंकि यह चुनाव का साल है। इसलिए आपने जितनी स्कीम्स बनाई हैं, वे सब इलैक्टोरेट्स को अपने पक्ष में करने के लिए बनाई हैं। अब जो आपकी कैश ट्रांसफर स्कीम्स आ रही हैं, उसकी जैनेसिस कर्ज़ा माफी की स्कीम से है। जिन पाँच राज्यों में आपको सबसे ज्यादा पोलिटिकल गेन्स की उम्मीद थी, वहाँ आपने कर्ज़े माफ किए और उनसे जो फायदा हुआ, वह आप सुन लीजिए। आंध्र प्रदेश में 11353 करोड़ रुपये का कर्ज़ा माफ किया। वहाँ 2004 में कांग्रेस के पास 29 लोक सभा सीटें थीं जो 2009 में 33 हो गईं। महाराष्ट्र में 8,953 करोड़ रुपये कर्ज़ा माफ किया। वहाँ इनके पास 13 सीटें थीं, जो 2009 में 17 हो गईं। उत्तर प्रदेश में आपने 9000 करोड़ रुपये बाँटे। वहाँ इनके पास 9 सीटें थीं, जो

बढक़र 22 हो गईं। केरल में 2962 करोड़ रुपये, और वहाँ आपके पास कोई सीट नहीं थी जो बढक़र 13 हो गईं। कर्ज़ा माफी में क्या हुआ, वह भी मैं आपको बताऊँगा। आपके रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर है जिस पर हम बहस कर चुके हैं। उसने कहा कि इतनी इर्रेगुलैरिटीज़ हुई हैं। जिनको नहीं मिलना था, उनको मिल गया और जिन्हें मिला था, उन्हें ज्यादा मिल गया। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलर निकाला कि 15 दिन के अंदर सबको पकड़ो। मुझे पता नहीं उसका क्या हुआ, अब तो उसको डेढ़–दो महीने हो गए हैं। आपकी जो स्कीम्स हैं, उनका नतीजा यही है। यह है आपका बजट। हाँ, लेटेस्ट है। महोदय, इन्होंने बजट में तीन मुद्दे छाँटे हैं – महिला, नौजवान और गरीब। सबको डायरैक्ट पैसा दो। ये कहते हैं कि स्किल्ड नौजवान पैदा करेंगे।

जितना भी दिया है वह दिया तो उसी काम के लिए है, मैं वह भी बता दूँ। सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि आप कहते हैं कि उनको स्किल्ड बनाएँगे और स्किल्ड बनाने के बाद उनको 10000 रुपये देंगे। आप उनको दिसम्बर–जनवरी तक स्किल्ड बना लेंगे और फरवरी–मार्च में उनको कहेंगे कि वोट करो। क्या आप लोगों को नासमझ समझते हैं? वे समझते नहीं कि आप क्या कर रहे हैं? मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसमें यह सब बताया गया है। उस रिपोर्ट में वैनेजुएला के इलैक्शन्स को स्टडी किया गया। उस रिपोर्ट में बताया गया कि वहाँ ऐसी स्कीम्स हैं जिनसे वोटर प्रभावित होता है। यह दूसरी रिपोर्ट आपको ज्यादा पसंद आएगी। आप उसको मानेंगे भी क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। हिन्दुस्तान की रिपोर्ट होती तो शायद आपको कम पसंद आती। यह रिपोर्ट कहती है:

"The results, however, show that the voters respond to targeted transfer and that these transfers can foster support for incumbent, thus making the case for designing political and legislative mechanism that avoid successful and anti-poverty scheme from being captured by political leadership."

तो यह उन्होंने पूरा किया है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन कैश ट्रांसफर्स वाली एक बात है। आप कहते हैं कि आपका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा। आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री के एक अफसर ने 'Strategy for doubling exports in next three years' बनाई। मुझे पता नहीं, उसका क्या है। ये अच्छे

अफसर हैं। मैं कॉमर्स कमेटी का चेयरमैन था तो ये आते थे।

There is a sensible person. यह रिपोर्ट बनायी है। आप एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट चिल्ला रहे हैं और आपका आदमी कह रहा है कि यह स्ट्रैटजी है। आप माने या न माने वह बात अलग है, लेकिन इस पर डिसक्शन तो करेंगे। बात तो होनी चाहिए कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़े? कौन सा बढ़े? किस चीज़ का बढ़े? उस एक्सपोर्ट से किस को काम मिलेगा? बंगाल की बहुत सी चीजें हैं, जिनको आप बढ़ावा दे सकते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या कौन सा ऐसा प्रदेश नहीं है, जहां की चीज़ आप बाहर नहीं भेज सकते हैं। आपको बहुत पैसा मिल सकता है, यदि आप टूरिज्म को डेवलप करें। भगवान ने आपको इतने प्राकृतिक संसाधन दिए हैं, जो कि परमानेंट हैं। उस पर आपका कोई खर्च नहीं होगा।

मैं बनारस शहर का प्रतिनिधित्व करता हूं, जहां हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। लेकिन आपका वहां ध्यान ही नहीं है। आपके पहले की रेल मंत्री ममता जी ने कहा था कि बनारस स्टेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो जाएगा। आज 2013 है और अब वह नेशनल का भी नहीं रहा। हर साल कहा जाता है कि वीवर्स के लिए यह होगा। मेरे यहां बहुत वीवर्स हैं। सारी बनारसी साड़ियां वहां बनती हैं। मेरे यहां बहुत ज्यादा तादाद में कारपेट बुनकर हैं, हेण्डलूम वीवर्स हैं। वहां से लेकर बिहार तक हेण्डलूम वीवर्स हैं मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में हेण्डलूम वीवर्स हैं। बंगाल में क्या बढिया साड़ियां बनती हैं मूंगा सिल्क, लेकिन सिल्क पर टैक्स बढ़ा दिया है।

मारबल पर भी आपने टैक्स बढ़ा दिया है। मुझे एक कवि मिल गए और कहने लगे कि साहब, अब तो इश्क करना भी फिजूल हो गया है, क्योंकि अब कोई भी आदमी इश्क में मकबरा नहीं बनवा पाएगा, क्योंकि मारबल इतना महंगा हो गया है। That is the type of reaction which people give. Your Budget has disappointed the entire country. मुझे पता नहीं कि प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी को यह पसंद आया है या नहीं, लेकिन देश में इसका भयंकर क्रिटीसिज्म है। सब यह कहते हैं कि यह चुनावी बजट है और कुछ नहीं है।

आपने एक महापुरुष के वक्तव्य से अपने भाषण का समापन किया था। आपने प्रतिरक्षा में चीन क्या कर रहा है या पाकिस्तान क्या रहा है, उसे देख कर आश्वासन दे दिया कि पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन डिफेंस जस का तस है। पैसे की कमी नहीं होगी, मगर तैयारी भी जस की तस है। संस्कृत

में एक कहावत है–

'kó.k j{kr% jk"V] vFk ppk çor%A
'kó.k j{kr% jk"V] 'kkó ppk çor%A
'kó.k j{kr% jk"V] jkT; ppk çor%A

जो देश वेल डिफेंडिड हैं, जिनकी आर्मी बहुत मजबूत है, वह शास्त्र चर्चा भी कर सकते हैं। They can discuss all the plans वह अर्थ चर्चा भी कर सकते हैं। being safe and secure- इकॉनामी का डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं। राज्य को समृद्ध भी बना सकते हैं। But the basic thing is that you must be well-protected and well-defended. रोज़ आप कांपते रहते हैं कि कभी चीन यह न कर दे, पाकिस्तान यह न कर दे। कहीं आतंकवादी न घुस जाएं। दिल्ली अनसेफ, मुम्बई अनसेफ है। कहां इकॉनामिक डेवलपमेंट है। आप बार–बार कहते हैं कि लोग नहीं आ रहे हैं, लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपकी नीतियां गलत हैं। आपके सिद्धांत और काम करने के तरीके गलत हैं। आपके यहां कौशिक बसु इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, जो बहुत दिनों तक आपके यहां रहे। उन्होंने क्या–क्या लिखा है, वह मैं बता दूं। वह यह कहते हैं कि आपके यहां जो सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, वह लैक ऑफ गवर्नेन्स से होती है।

वह यह कहता है कि

> "If you want to start a business in India, it will take you an average 88 days to get the clearance. In China it takes 46 days; in Malaysia 31 days; and in Singapore 8 days. If your business runs into a problem of contract violation, in India, it will take you a year to solve the problem; in China 180 days; in Singapore 50 days. But if you can have contracts enforced and start a business, the real catch in India is going out of business. To resolve an in solvency case and shut down a firm, it takes 7 months in Singapore; 26 months in Malaysia; in India a little over than 11 years."

यहां कौन करेगा बिजनेस? आप इसे सुधारिए और इस में एफडीआई लाओ इत्यादि बंद कीजिए। आप पहले अपनी सरकार को सुधारिए। अपनी

फाइनैंशिएल गवर्नेंस को सुधारिए। आपकी मिनिस्ट्री Constitutional violence करती है। आप Consolidated Fund of India से पैसा निकालते हैं। उसे खर्च दिखा देते हैं। आप यही कर रहे हैं। प्लीज़, प्लीज़, कम से कम फाइनैंस मिनिस्ट्री को फाइनैंस के मामले में Constitution का violation नहीं करना चाहिए। we have examined this issue in detail.we have submitted a Report. संविधान का भी मज़ाक उड़ा दिया। आपकी मिनिस्ट्रीज टाईम पर जवाब नहीं देती है। दो बातें कह कर मैं अपना भाषण खत्म करूंगा।

पहली बात तो यह कि जो इस मामले में हमारे देश के एक बड़े विद्वान थे – कौटिल्य। Hesaid:

"The king is advised, that is the ruler of the Government is advised, to be ever active in the management of the economy because the root of wealth is economic activity. In activity brings material distress. without an active policy, both current prosperity and future gains will be destroyed."

He further more said about the responsibility of audits and accounts:

"Accounts officers shall present themselves for audit at the appointed time, bringing with them their account books and the income to be related to the treasury. Be ready for the audit when the audit officers call him."

यह क्या हो रहा है? ऑडिट कहता है कि मैं ऑडिट करना चाहता हूं। सरकार कहती है कि मत करो, यह नहीं कर सकते। फौज़ वाले कहते हैं कि इधर मत देखो। इंडस्ट्री कहती है ज्वायंट वेन्चर को मत देखो। सरकार कहती है कि अगर तुम इसे देख रहे हो तो तुम हमें de-stablilise कर रहे हो, तुम ऑपोजीशन से मिल गए हो। क्या बात है? He further more said:

"Be ready for the audit when the audit officers call him; not lie about the accounts when questioned during audit; and do not try to interpolate an entryas

if it was forgotten in advertently. Failure to conform toany of the regulations is a punishable offence.

In case a discrepancy is discovered during audit, the official concerned shall pay a penalty if the discrepancy has the affect of either showing a higher income or a lower actual income, in both the cases the State being the loser."

You, as a Finance Minister, have double duty. On the one hand you have to see that the money is collected and on the other hand you have to see that the money is properly spent and accounted and then get it submitted for the audit. Do not decline the Auditor; do not denigrate that Constitutional Office; and finally, fight out the corruption. I will not deal with that in detail because it has been dealt in so many debates. Please revise your Budget that you can and bring principles into it. If I remember, you have quoted Swami Vivekananda.

I also finish my speech with the quotation from Swami Vivekananda. Itsays:

"I am one of the proudest men ever born, but let me tell you frankly, it is not for myself, but on account of my ancestry.

Do not be in a hurry, do not go out to imitate any body else. This is another great lesson we have to remember; imitation is not civilization.

Oh India,with this blind imitation of foreigners, this blind dependence on foreigners, this slave like weakness, this cowardice, do you wish to achieve great heights?"

Mr. Finance Minister, do not depend too much upon the foreign wisdom; upon the foreign money. Try to invoke the inner strength of India,which you have said that you want to do but your Budget miserably fails. I am sorry to

say this.

I wish, if you could have stood up to that quotation from Swami Vivekananda. The Budget is totally in contradiction to what you have said in the end. I wish that that should have been the real theme of your Budget, the real theme of any Indian Budget. In the times to come, we should not imitate; imitation is not civilization. Let us try to realize our own inner strength, the vitality of India, Mr. Finance Minister. It is the civilizational consciousness of India which has to be rekindled and reawakened. And with that spirit, if you come before the nation, I think, the nation will respondas it responded to Lal Bahadur ji, as it responded to Atal Bihari ji.

Mr. Finance Minister, please takea fresh view; come with another revised version of your Budget Speech, if you can; otherwise this would be your last Budget!

Thank you.

■

बड़ी–बड़ी बातें करना छोड़ दो और धरातल पर आ जाओ

lfe=k egktu

Vध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष 2013–14 के बजट पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। इस बजट में बहुत–सी बातें कही गई हैं। अगर बजट का वर्णन अगर दो शब्दों में कर दिया जाए, तो यह होगा कि यह बजट बोल बजट है। करना कुछ नहीं है, परिणाम लाना नहीं है, जिम्मेदारी उठानी नहीं है, तो बोलने में क्यों कंजूसी। बोलते जाना है कि कहीं इधर दो सौ करोड़, कहीं उधर दो सौ करोड़, कहीं हजार करोड़। सभी जगह बांटते जाओ, क्योंकि दो–तीन महीने बाद या अगले चुनाव में बोरिया–बिस्तर बांध कर जाना ही है। वास्तव में देखा जाए, तो यही भाव पूरे बजट है। हम प्लान एक्सपेंडिचर देखते हैं 5.55 लाख करोड़ और नॉन प्लान 18 लाख करोड़ रुपए के आस–पास है। पूरे बजट में प्लान बजट बढ़ाने का कहीं प्रयास भी नहीं दिख रहा है, ऐसा यह पूरा बजट है। वास्तव में होना यह चाहिए था कि आज महंगाई से देश त्रस्त है।

मगर महंगाई कम करने के लिए बजट में कुछ भी नहीं किया गया है। 80000 करोड़ रुपया रूरल के लिए जरूर रखा गया है, बढ़ाकर रखा गया है लेकिन मैं स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन हूं और मुझे पता है कि जितना भी बजट रखा जाता है, पहला जो हमेशा अनुभव यह रहा है कि पूरे फंड्स का उपयोग नहीं हो पाता है। मिसमैनेजमेंट होता है। कई जगह भ्रष्टाचार भी हो सकता है। नॉन–इम्पलीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स भी रहता है। इन सब बातों से रूरल डवलपमेंट के प्लान्स भरे रहते हैं और उनको ठीक करने के लिए कोई

भी स्टैप्स इस बजट में नहीं उठाये गये हैं।

हमारे वित्त मंत्री जी बहुत अच्छी बात करते हैं। आज की तारीख में टैक्नोलॉजी के हिसाब से हमारी पोजीशन दसवें स्थान पर है और मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता है लेकिन उसको पांचवें स्थान पर लाने की बात हो रही है। मगर पांचवे स्थान पर लाने के लिए क्या कदम उठाएंगे, इसकी कोई भी बात नहीं कही गई है।

गरीबों के लिए जो फूड सिक्योरिटी की बात कही जाती है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। वास्तव में, आज की तारीख में हमारे देश में अनाज की कमी नहीं है। हमारे यहां के किसान और विशेषकर मध्य प्रदेश के किसान बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे यहां अनाज की कोई कमी नहीं है। हमारे यहां के गोदाम भरे पड़े हैं लेकिन वहां अनाज सड़ रहा है। बांटा नहीं जा रहा है। उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं। मगर जो हमारे पास आज की तारीख में अनाज है, हम उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? हमारे किसान जो मेहनत कर रहे हैं, उस किसान को मेहनत का फल मिले, उसके लिए हम क्या करेंगे? मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी क्योंकि ये अंग्रेजी में अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। न्यूट्रिशन की बात कही गई है और उसमे कहा है कि:

"We start a pilot programme on Nutri-Farms for introducing new crop varieties that are rich in micro-nutrients such as iron-rich bajra, protein-rich maizeand zinc-rich wheat."

मैं अपने अनुभव की बात करना चाहूंगी। बाजरा ज्वार इत्यादि की जो बातें आप कर रहे हैं और इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारी कृषि नीति इतनी गलत है कि इसके कारण जो हम कहते हैं कि ज्वार, बाजरा, काला चना, लाल चना इत्यादि चीजें हमारे यहां होती हैं, मैं अब बताना चाहूंगी कि ये सब चीजें गायब होती जा रही हैं। अब ये 200 करोड़ रखकर न्यूट्रिशन की बात यह सरकार जो कर रही है, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन आज की तारीख में मेरे क्षेत्र में ज्वार के खेत ही खेत थे लेकिन मैंने हमारे यहां के किसानों को कहा कि कुछ साल बाद ऐसी बात आएगी कि ज्वार एक ऐसी डिब्बी में रखकर आने वाली पीढ़ी को दिखानी पड़ेगी कि इसको ज्वार कहते हैं। यह ज्वार, बाजरा, नाचनी जो महाराष्ट्र के लोगों में और आदिवासी लोगों में बहुत यूज होती है। नाचनी खाकर ही आदिवासी

लोग पुष्ट हुआ करते थे। मगर अब वो नाचनी नहीं दिखेगी क्योंकि किसान उसे नहीं उगाते हैं। किसानों को उनकी फसल की कीमत नहीं मिलती है। आप न्यूट्री फूड की बात करते हैं। आज की तारीख में हम देखते हैं कि जैविक फूड की भी बात कही जाती है।

वास्तव में आज आवश्यकता जैविक फूड की आ गई है क्योंकि जिस प्रकार से अलग अलग चीजें डालकर हमने अपने खेतों को खराब किया है, हमारे यहां के लोग कहते हैं कि बाजार से सब्जी लाने के तुरंत बाद ही उस सब्जी को मत पकाओ क्योंकि उस पर बहुत कुछ पेस्टीसाइड्स का छिड़काव किया गया है। लेकिन जब मैं बात जैविक खेती की करती हूं तो आज की तारीख में जो लोग हैं, वे कहते हैं कि हम उगाने के लिए तैयार हैं लेकिन हमारे यहां कोई ऐसी भी लैब नहीं है कि जो यह सर्टिफाइ कर सके कि यह जो उत्पादन है, इसकी कीमत यह होनी चाहिए और हमें उसकी कीमत नहीं मिलेगी। यील्ड थोड़ा कम होता है। इसलिए कम यील्ड वाली बातें नहीं चलतीं। किसानों को वैसे ही पैसा कम मिलता है। मैं पूरी एक नीति की बात कर रही हूं। आप केवल न्यूट्री फूड की बात कर रहे हैं, लेकिन जो फसलें इस प्रकार से गायब हो रही हैं, यह चिन्तनीय है।

मेरे अपने क्षेत्र में डालर चना आ गया है। यह कहा जाता है एक्सपोर्ट होता है, पैसे मिलते हैं। लाल छोटा चना जिसे हरभरा कहते हैं, वास्तव में न्यूट्रिशियस है लेकिन गायब होता जा रहा है। मेरे क्षेत्र में सोयाबीन बहुत उगा रहे हैं लेकिन इसका उपयोग केवल तेल निकालने के लिए होता है और बाकी एक्सट्रेक्ट बचता विदेशों में जाता है। हमारे यहां इससे न्यूट्रिशियस फूड, बाए प्रोडक्ट बनना चाहिए, उसके लिए कुछ नहीं है। मैंने बोल बजट इसलिए कहा कि केवल 200 करोड़ रखो, बड़ी बात कहो, इससे कुछ नहीं होना है। वास्तव में नीति इस प्रकार की होनी चाहिए कि किसान उस दिशा में जाए। लेकिन उस तरह की बातें बजट में नहीं हैं। हर घर में लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं।

महोदया, मेरे दोनों साथियों ने बहुत विस्तार से बातें कही हैं इसलिए मैं सब बातें न कहते हुए केवल एक मुद्दे के बारे में भाषण में कहने वाली हूं और वह मुद्दा महिलाओं का है। वित्त मंत्री जी ने बड़े आत्ममुग्ध होकर ने महिलाओं की बात कही। उन्होंने कहा -Three faces of India. One is woman; second one is youth and the third one is poor. थ्री फेसिस आफ इंडिया के लिए बड़ी बात कही गई, Gender-related aspects of

empowerment. उन्होंने इसका उल्लेख अपने भाषण में किया है। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि वैसे तो कांग्रेस की सरकार सालों साल से है, अब तो कांग्रेस 115 साल की हो गई है। मगर 115 साल की होते इतनी पिछड़ रही है कि अपने साथ देश को भी पछाड़ रही है। वित्त मंत्री जी, आप अगर अपने से पहले लोगों से समझिए। मैंने आत्म मुग्ध शब्द के बारे में कहा यानी आप आत्म मुग्ध मत बनो यानी जो कुछ हूं मैं ही हूं, मैं जो बोलता हूं वही बहुत अच्छी बात है। नहीं। आपसे पहले भी कई लोगों ने महिलाओं के लिए अच्छी बातें कही हैं और की हैं। जेंडर बजटिंग की बात होती है। किसी ने शब्द का प्रयोग किया होगा, जब मैं महिला बाल विकास मंत्री थी, यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री थे, उस समय हमने जेंडर बजटिंग की शुरुआत की थी। हमने केवल बातों में नहीं कहा था। हमने नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनेंस एंड पालिसी कांस्टीट्यूट की थी। यह कहा था कि इस विषय पर पूरा अभ्यास करें, स्टडी करे प्लानिंग बनाएं। हमने श्री के.सी. पंत जी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाई थी। मेरे पास महिला बाल विकास मंत्रालय के पेपर्स है, अगर वित्त मंत्री जी चाहें तो मैं देने को तैयार हूं। हमने वूमेन एम्पावरमेंट ईयर मनाया था। हमने महिला सशक्तिकरण, स्वयं सिद्धा, स्वाधार और कई प्रकार की योजनाएं बनाई थीं। योजनाएं बनाकर लागू की थी। उस समय हमने स्टडी की थी और कई बातें पाई थी। महिला बाल विकास का बजट बढ़ाया था। महिलाओं का विकास कैसे होता है, हर काम में उनकी भागीदारी, हिस्सेदारी कैसे हो सकती है, इस पर स्टडी की। उस समय हमने काम किया था और आंगनवाड़ियों की शुरुआत हुई थी। अब गांव–गांव में आंगनवाड़ियों में महिला उत्थान और बच्चों की देखरेख होती है। अगर किसी ने उसके लिए सोचा गया था तो केवल और केवल माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में सोचा गया था। पहली बार हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता का मानदेय बढ़ाया था। हम केवल वहीं पर नहीं रुके बल्कि महिलाओं को स्त्री शक्ति पुरस्कार दिए ताकि उनके अच्छे कामों को रिकोग्नाइज किया जा सके। मैं यशवंत सिन्हा जी की आभारी हूं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जिला, राज्य और नेशनल स्तर पर पुरस्कृत करने की योजना बनाई गई थी। इसके आगे जाकर नौंवे प्लान में वूमेन कम्पोनेंट प्लान की बात की गई थी। हमने इसे लागू किया। हमारे समय में इस पर स्टडी हुई और इसे देखा गया था। उस समय की बात है – not less than 30 per cent of the funds should be specifically earmarked

for women's programmes.

यह बात उस समय कही गई थी। उसे लागू करने की दृष्टि से हमने काम शुरू किया था। मैंने जैसे कहा कि महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत यह पालिसी बनाने की बात थी और उस पर स्टडी शुरू की। हमने कहा कि हर साल के बजट को जेंडर बजटिंग की दृष्टि से हम स्टडी करें और केवल महिला बाल विकास मंत्रालय ही नहीं, बल्कि जो–जो ऐसे मंत्रालय हैं, जहां महिलाओं पर आधारित प्रोग्राम चलाये जाते हैं, ऐसी कई सारी मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे वह एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, चाहे सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री हो, पांच–छः एचआरडी मिनिस्ट्रीज हैं, पांच–छः ऐसे मंत्रालय हैं कि जहां इस प्रकार की बात हो सकती है कि जिसमें वूमैन्स के प्रोग्राम्स चलाये जाते हैं, हमने उनकी स्टडी करते हुए हर साल बढ़ाया। हमें केवल चार–पांच साल ही मिले थे। हमें मालूम कि डिफैंस जैसी मिनिस्ट्री में हम वूमैन कम्पोनैन्ट की बात नहीं कर सकते। मगर जहां कर सकते हैं, वहां कैसे काम हो सकता है, कैसे होना चाहिए, इस पर ध्यान देते हुए हम 23 परसैन्ट तक बढ गये थे। हम 30 परसैन्ट नहीं बढ़ पाये, लेकिन 23 परसैन्ट तक हम आये थे, यानी यह इनक्रीज हुआ था। मेरे पास इसकी पूरी रिपोर्ट्स हैं। मगर मैं इतना ही बताना चाहूंगी कि 2003–2004 तक हमने ये सब काम करके दिखाये थे। जेंडर बजटिंग जब हम करते हैं तो वित्त मंत्री जी मैं जैसे बहुत समझदार और पढ़ी–लिखी नहीं हूं, लेकिन उसका अर्थ यह होता है कि कैसे महिलाओं के उत्थान की दृटि से हर मंत्रालय में काम कैसे हो। कानून की दृष्टि से भी हमने उस समय विचार किया था और यह करते–करते जैसे मैने कहा कि 23 परसैन्ट तक हम बढ़ गये थे। लेकिन आज आपकी क्या स्थिति है। आज आप क्या करते हो। देखो बात बहुत सुंदर करते हैं और करते क्या हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा –womenare the heads of many banks. बैक की बात करते हुए उन्होंने वूमैन सैल्फ हैल्प ग्रुप को सपोर्ट करने की दृटि से कहा, जो महिला बैंक की आपने कही, सैल्फ हैल्प ग्रुप को सपोर्ट करने की दृटि से वूमैन्स लाइवलीहुड को सपोर्ट करने की दृटि से आपने कहा। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, शायद आपको मालूम नहीं होगा। महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत राट्रीय महिला को नाम की एक चीज है। 1993–95 में राट्रीय महिला को की वास्तव में शुरूआत हुई थी। यह बात भी हुई थी कि इसे सौ करोड़ रुपये तक ले जाना है। जब तक आप लोग थे, नहीं ले गये थे, लेकिन हमारे दोनों वित्त मंत्री, श्री यशवंत

सिन्हा और श्री जसवंत सिंह जी ने तय किया था कि महिलाओं के लिए कुछ करेंगे। वे इसका पूरा प्लान सौ करोड़ तक ले गये थे। राष्ट्रीय महिला को में वास्तव में जो सुदूर गांवों में बैठे हुए सैल्फ हैल्प ग्रुप्स हैं, छोटे–छोटे एनजीओज हैं, वे अपने दम पर खड़े हो जाएं, इसलिए राष्ट्रीय महिला को काम करता है। मुझे मालूम नहीं है आज आपने इस पर कितना ध्यान दिया है। मगर आप क्या बात कर रहे हो, आप यह बात कर रहे हो –support to SHG sand women's livelihood that employs predominantly women and that address gender related aspects of empowerment and financial inclusion. लेकिन उसके लिए आपने क्या किया, आपने एक महिला बैंक की स्थापना, उसके लिए आपने एक हजार करोड़ रुपये रखे। इसका स्वागत है, क्योंकि मैं ऐसी महिला हूं कि महिलाओं के आप जो भी कुछ करोगे, हम उसका स्वागत ही करेंगे। लेकिन थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिये कि जब आप महिलाओं के लिए बैंक की स्थापना करते हो, जब आपने इसकी घोषणा की तो हमने, सुषमा जी और सबने तालियां बजाईं और इसका स्वागत किया। लेकिन क्या यह वूमैन एम्पावरमैन्ट के लिए आन्सर है, क्या यह आन्सर हैं जेंडर बजटिंग के लिए। करने के लिए वित्त मंत्री जी बहुत काम हैं, आप ही खोलकर देखिये, आपके यहां आरबीआई और नाबार्ड की इश्यु की हुई गाइडलाइंस हैं, अगर आप उनका भी पालन करें तो बहुत कुछ हो जायेगा। उसमें यह कहा गया है कि महिला उद्यमियों को प्रायोरिटी दी जाए।

इसके अलावा वूमैन्स डैस्क की बात की गई है। यह महिला डैस्क क्या है। जहां–जहां भी बैंक्स हैं, सुदूर गांव–गांव में जो–जो बैंक्स हैं, वहां महिला डैस्क स्थापित कीजिए, यह आपकी गाइडलाइंस में है। लेकिन उसको पढ़िए तो सही, वित्त मंत्री जी आप तो बहुत पढ़े–लिखे हैं। मगर छोटी बातें पढ़ा कीजिए। लोगों की समझ की बातें पढ़ा कीजिए। जो लोगों के काम आएं, ऐसी बातें पढ़ा कीजिए। महिला सशक्तिकरण कब होगा? एक महिला बैंक मुंबई में स्थापित है। मुंबई में तो महिलाएं बैंक में जाती ही हैं। मगर गांव–गांव में जो बैंक हैं, उसमें यह गाइडलाइन है कि बैंक में एक महिला डेस्क की स्थापना करनी चाहिए और वहां पर आवश्यक रूप से लोकल भाषा जानने वाली महिला को काम देना चाहिए, ताकि जब महिलाएं वहां पर काम के लिए आएं, वह लोन काम हो या अन्य कोई भी काम हो, वे आसानी से उनकी बात को समझ सकें, आसानी से उसका बैंक तक एक्सेस हो जाए। आप महिला

सशक्तिकरण की बात करते हैं तो वह केवल एक महिला बैंक स्थापित करने से ही नहीं होगा, कुछ और भी सोचना पड़ेगा। अभी तो आप उस पर एक घनाघात करने जा रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स का। मैं आज बाकी कोऑपरेटिव बैंक्स की बात नहीं करूंगी। मगर कहीं महिला कोऑपरेटव बैंक है, महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जो वास्तव में गांवों में काम करती हैं, जहां उनकी जरूरत है। मुंबई के महिला बैंक में आ कर महिला सशक्त होने वाली नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि आपके जो नैशनलाइज़ बैंक्स हैं, आज आप अगर उनकी वर्किंग देखेंगे, जिस तरीके से वहां भी जो एनपीए बढ रहा है, जिस तरीके से वहां पर ऋण बांटा जा रहा है। वहां पर फेवरेटिज्म होता है। आप उसको कंट्रोल करना सीखें। कोऑपरेटिव बैंक तो भंग होते हैं। कोऑपरेटिव बैंकों के अध्यक्ष तो तुरंत जेल में भी जाते हैं। ठीक है जाना चाहिए, मैं उनका बचाव नहीं कर रही हूँ। लेकिन बताइए कि नैशनलाइज़ बैंक्स के वे लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वे लोग जो ऐसे लोन देने में माहिर हैं, जिन्होंने ऐसे लोन दिए है, जिनके कारण एनपीए बढ़ा है, उनके खिलाफ कितनी इंक्वायरी हुई है? ऐसे कितने लोग जेल में गए हैं? उस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। एक महिला बैंक स्थापित करने से क्या महिला सशक्तिकरण होगा? मुंबई की वह महिला तो आगे बढ ही रही है। वह बैंक में जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि जो छोटे–छोटे कोऑपरेटिव बैंक हैं, महिला कोऑपरेटिव बैंक हैं, निवेदिता कोऑपरेटिव बैंक है, धरमपेठ महिला कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, कई सारी ऐसी सोसाइटी हैं, आपको भी मालूम होगी, आपके वहां पर भी होगी। आप उनको बढ़ाने के लिए कुछ कदम क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि वे गांव–गांव में काम करती है। वह गांव–गांव की महिलाओं की प्रिय बनती है। गांवों की महिलाएं आत्मविश्वास के साथ वहां पर जाती हैं। मगर आपको तो वह काम नहीं करना है। इंकम टैक्स वगैरह तो छोड़िए। कोऑपरेटिव पर आप घनाघात करने पर तुले हुए हैं। वहां तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो करने लायक काम हैं, वह नहीं कर रहे हैं। अगर आप वास्तव में महिला सशक्तिकरण चाहते हैं, तो इन छोटी–छोटी बातों पर ध्यान देंगें तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। लेकिन आज महिला के नाम कितनी प्रापर्टी है? कितने मकान हैं? कितनी जमीन है? वह कहां से लोन लेगी? वह क्या करेगी? इन विषयों पर भी तो सोचना बहुत आवश्यक है। हम नहीं सोच रहे हैं।

अध्यक्षा जी, जैसे मैंने कहा कि सौ करोड़ या दो सौ करोड़ रुपये बांट

रहे हैं। इन्होंने एक बात और कही है कि "I propose to set apart Rs.200 crore to fund organisation…" ये साइंस एण्ड टैक्नॉलाजी की बात कर रहे हैं। मगर आप सामान्य व्यक्ति की जहां बात कर रहे हैं – "…to set up and make these products available.." आप ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, जो सामान्य लोगों के काम आते हैं और वे ऐसे बनें, इसके लिए आपने दो करोड़ की बात कही है। एक अलग ऑर्गनाइज़ेशन की बात कही है। जब मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, तब हम इन सुझावों को दे चुके हैं, यह सब हम कर चुके हैं। बैंगलोर में ही हमने साइंस एण्ड टैक्नॉलाजी की एक कॉन्फ्रेंस की थी। उस समय हमने कहा था कि अगर महिलाओं की मदद करनी है तो वूमन फ्रेन्डली टैक्नॉलाजी की बात करो। मदद कैसे कर सकते हैं? महिलाएं खेतों में सबसे ज्यादा काम करती हैं।

मेरे पास नर्सरी में काम करने वाली महिलाएं आयी थीं। वे खुरपियों से प्लास्टिक की थैली में भरती हैं और प्लान्ट्स वहां पर सुरक्षित करती हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह हमारे लायक छोटी खुरपी बने तो प्लास्टिक की थैलियां दिन में हम ज्यादा भर सकते हैं, गिनती के अनुसार हमें ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। आप ऐसा करो। आज एग्रीकल्चर में जो भी टेक्नॉलाजी है, नए–नए खेती के प्रयोजन हैं, उसका एक्सेस महिलाओं तक बढ़ाओ। महिलायें सबसे ज्यादा खेती के काम को करती हैं, उन्नत खेती कैसी हो, महिलाओं को सिखाओ।

महोदया, मैं एक छोटी सी बात बताती हूं, बात बहुत छोटी है, मगर महिलाओं की दृष्टि से बहुत काम की थी, मैंने बंगलौर में यह बात समझी थी। वहां कुछ सब्जी वाली महिलायें मुझसे मिलने आयीं। उन्होंने कहा कि हम खेतों में सब्जियां उगाते हैं और वह सब्जियां भर–भर कर हम मार्केट में ले जाते हैं। हमारी बड़ी–बड़ी टोकरियां रहती हैं। हम जब बस में चढते हैं, टोकरी बस की छत के ऊपर रखनी पड़ती है और उसे चढ़ाने में हमें बहुत तकलीफ होती है। जो पुरूष उसे चढ़ाने वाला होता है, मैं यहां वर्णन नहीं करना चाहती, गिरिजा जी जैसा बोलीं कि टोकरी चढ़ाते समय चाहे जैसा व्यवहार होता हो, तो मैंने कहा कि फिर आप चाहती क्या हैं? वे बोली, हमने सुना है कि यहां बड़े–बड़े साइंटिस्ट आए हैं, आप कुछ करने और सोचने वाले हैं, आप ऐसी बस क्यों नहीं बनाते हो, हमें बैठने की जगह नहीं चाहिए, हमें ऐसी बस बनाकर दो कि बस के अंदर ऐसे स्टैंड हो, जिन पर हम अपनी

टोकरी रखें और हम खड़े–खड़े जाएं। यह एक सोचने लायक बात उन महिलाओं ने बतायी। मैं जो कह रही हूं कि वूमेन फ्रैंडली टेक्नॉलाजी की बात करो, यह मैं अनुभव से कह रही हूं। केवल 200 करोड़ रूपए देकर, कोई कुछ इन्नोवेट कर रहा है, उसको पुरस्कार दो, उसे खरीदो, यह न हो, हमें इस पर कुछ प्रयास करना चाहिए, मुझे यही कहना है।

महोदया, मैं एक बात और कहूंगी, इन्होंने थ्री फेजेज के बारे में कहा, मैं युवाओं की बात कहना चाहूंगी, एक हजार करोड़ से तो युवाओं की बात बननी ही नहीं है। अगर मैं कहूंगी कि आप मोदी जी से इस बात को समझो तो आपको बात गलत लगेगी। उन्होंने तो आठ सौ करोड़ रूपए एक स्टेट में ही रखे और आप एक हजार करोड़ रूपए पूरे देश के लिए रख रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए एचआरडी के अंतर्गत जो जनशिक्षण संस्थान हैं, आप उनको ताकतवर कीजिए। जो पहले से हैं, उन्हें आप ताकतवर करेंगे नहीं और नयी–नयी बातें करते जाना है। मेरा यही कहना है कि आप युवाओं ताकतवर कीजिए। युवा भी इतने ज्यादा हैं, अगर वर्किंग ऐज की बात करो, तो 64 परसेंट होने वाले हैं, आप उनके लिए क्या करेंगे? मैं आज केवल एक ही बात करूंगी कि आप महिलाओं की बात करते हो, गरीबों की बात करते हो, एक पुअर मैन का चेहरा इन्होंने कहा, तीन फेजेज इनके ध्यान में हैं, लेकिन थ्री फेजेज को ध्यान में रखकर आपने किया क्या? आज सबसे बड़ी बात महंगाई की जो मैंने की, मैं बाकी महंगाई की बात नहीं करती हूं, वह तो है ही, चल ही रही है, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया है। मगर हम कैसे सोचते थे, ऐसा बार–बार आपको लगेगा, आखिरी के साल भर अटल जी ने मुझे पैट्रोलियम मिनिस्ट्री में भी रखा। जब हम पैट्रोलियम मिनिस्ट्री में थे तब हमने उस समय शुरू की, कि गरीब आदमी क्या करे, अगर वह पूरा का पूरा सिलेंडर नहीं ले सकता है तो हमने उसके लिए पांच किलो के सिलेंडर की शुरूआत की थी। हमने यह सोचा कि वह पांच किलो वाला सिलेंडर ही लेकर चला जाये। आज मेरे पास लोग आते हैं कि आज अगर गैस सिलेंडर महंगा है, आप बोलते हो कि 9 सिलेंडर देने हैं, 10 सिलेंडर देने हैं 12 सिलेंडर देने हैं तो फिर उसके बाद क्या? महोदया, मैं कहना चाहती हूं कि ये गरीब आदमी के लिए कब सोचेंगे? आप ऐसी फिलिंग की व्यवस्था करें कि अगर मेरे पास पांच सौ रूपये या दो सौ रूपये हैं तो मैं उतना ही गैस भरूं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? हमने पांच किलो के सिलेंडर की बात की, आप क्यों नहीं उसे आगे बढ़ा सकते हैं?

महोदया, मेरा इतना ही कहना है कि ये जिस तरीके से इन्होंने बातें की हैं, बड़ी–बड़ी बातें की हैं, मेरा इनसे इतना ही कहना है कि ये बड़ी–बड़ी बातें करना छोड़ दो और धरातल पर आ जाओ। महोदया, इनके प्रिय थिरूवल्लुवर हैं, हमारे भी प्रिय हैं, वे केवल कवि ही नहीं थे, वे महान ऋषि तुल्य कवि थे। वे दो हजार साल पहले बहुत कुछ कहकर गये। आप उनकी कविता पढते तो हो, मगर जो आपको सुहावनी लगती है, वह पढ़ते हो, जो वास्तव में पढ़नी चाहिए, वह कविता, वह वर्ज़न पढ़ो। मैं तमिल तो नहीं पढ सकती हूं, लेकिन उसका हिन्दी वर्ज़न आपको पढ़कर बताऊंगी, शायद 196 या 197 पैराग्राफ का नम्बर है, आप घर जाकर उनकी किताब में देख लेना। उन्होंने एक बात कही, ध्यान रखिए वित्त मंत्री जी, आपके ही थिरूवल्लुवर ने थिरूकुलर में यह बात कही है। उसमें उन्होंने तमिल में कुछ कहा। मैं उसको इतना ज्यादा नहीं समझ सकती मगर हिन्दी में उसका जो अनुवाद है –

'लंबी चौड़ी बात जो होती अर्थ विहीन
घोषित करती है वही, वक्ता नीति विहीन।

इससे भी यादा एक कड़वी बात उन्होंने कही। वित्त मंत्री जी उसे भी घर जाकर शांति से पढ़ें –

'जिसको निष्फल शब्द में..
क्योंकि इनके बजट के सभी शब्द निष्फल हैं।
'जिसको निष्फल शब्द में रहती है आसक्ति
कहना ना तू उसको मनुज, कहना थोथा व्यक्ति।

ऐसा थिरुवल्लुवर ने कहा था। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।

■

आपका बजट नौकरशाही उन्मुखी है

gDeno ukjk;.k ;kno

महोदय, हमारे सामने जो बजट पर सामान्य चर्चा की जा रही है, चूंकि यह बजट पर सामान्य चर्चा है, इसलिए करीब–करीब सरकार के मातहत जितने विषय हैं, उन सभी विषयों पर इसमें चर्चा हो जाती है। वित्त मंत्री जी अमेरिका से पढ़े हुए अर्थशास्त्री हैं, विद्वान हैं, मैं उनके अर्थशास्त्र की विद्या को नमस्कार करता हूं। मैं जो कुछ भी कहूंगा, वह उनके जैसे ही महान विद्वान जर्मनी से पीएचडी किये हुए महान स्वतंत्रता सेनानी डॉ0 राममनोहर लोहिया के कुछ प्रसंगों को उनके सामने रखता चला जाऊंगा। जब कभी हम बात करते हैं तो हिन्दुस्तान के गांव, गरीब, किसान, पिछड़े, दलित, बनवासी की बात करते हैं। हिन्दुस्तान में जब यह बजट बना है तो यहां दो बातों का संघर्ष है। एक तरफ हिन्दुस्तान में पसीने वाले लोग हैं और एक तरफ हिन्दुस्तान में पैसे वाले लोग हैं।

पैसे वाले के तन से पसीना नहीं आता, पसीना बहाने वाले के पास पैसा नहीं जाता। जो पसीने से लथपथ रहता है, जेठ की चिलचिलाती दुपहरी में अपने शरीर को झुलसाता है, पानी में अपने शरीर को गलाता है, जाड़े में अपनी हड्डी को ठिठुराता है, उसी पर रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था –

'कुत्ते को मिलता दूध–भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं,
माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर, जाड़े की रात बिताते हैं।
हटो स्वर्ग के दूत, मैं स्वर्ग लूटने आता हूँ।

आज हिन्दुस्तान की जो तस्वीर है, उस तस्वीर पर क्या अर्थशास्त्री, वित्त मंत्री और हमारे महान् अर्थशास्त्री प्रधान मंत्री का क्या कभी ध्यान जाता है? अर्थशास्त्र भी कई तरह के हैं। एक है ग्रामीण कृषि अर्थशास्त्र और एक है औद्योगिक पूँजीपति अर्थशास्त्र। डॉ. लोहिया ने कहा था – 'आग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रह और अनुग्रह से प्रेरित होकर इस देश में सत्ता को चलाया जाता है। एक तरफ इनके मन में कुछ लोगों के प्रति पूर्वाग्रह और दुराग्रह है। जैसे पिछड़ी जाति, दलित और वनवासी के लिए मन में यह दुराग्रह है कि उनके घर में कोई तेजस्वी, कोई प्रतिभाशाली, कोई योग्य, कोई दक्ष और कोई सक्षम पैदा हो ही नहीं सकता है। इस दुराग्रह से प्रेरित होकर ये सरकार को चलाते हैं और समाज को बनाते हैं तो यह देश कैसे बन सकेगा? एक तरफ कुछ लोगों के प्रति दुराग्रह और पूर्वाग्रह है – गाँव, गरीब, किसान और मज़दूर के प्रति पूर्वाग्रह और दुराग्रह है कि उनका जितना शोषण कर सकते हो करो, ये बोलेंगे क्या? जाति के दलदल में ये इतने धँसे हुए हैं और दलों के बीच में ये इतने बँटे हुए हैं कि ये न कभी एकजुट होंगे, न इकट्ठा होंगे। जब वोट का समय आएगा, जाति का रस्सा लेकर जाएँगे और सबको फँसाएँगे और चिड़िमार के जैसे सबकी गर्दन मरोड़कर रख देंगे, लेकिन हिन्दुस्तान के बजट को उन पूँजीपतियों के लिए बनाएँगे – कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। आपकी दृष्टि कहीं है और काम किसी के लिए करते हैं। इसलिए मैं इनसे कहना चाहूँगा कि ये समाजवाद की चर्चा करते हैं। मैंने इस संसद में पढक़र बताया था। मैं फिर उन पंक्तियों को पढक़र बता देना चाहता हूँ कि इन विद्वान अर्थशास्त्रियों के बीच में एक समाजवादी, महान् स्वतंत्रता सेनानी, गांधी जी के साथ रहने वाले, नेहरू के आनन्द भवन में विदेश सचिव का कार्यभार सँभालने वाले, ऐसे महान् अर्थशास्त्री विद्वान डॉ. लोहिया ने समाजवाद के बारे में क्या कहा था, ज़रा सुनें।

> 'समाजवाद हर किसी अन्य सिद्धांत की तरह एक होता है थोक, एक होता है फुटकर, एक होता है सगुण, एक होता है निर्गुण, एक होता है सिद्धांत, एक होता है कार्यक्रम। समाजवाद से एक सीढ़ी नीचे उतरो। उस सीढ़ी का नाम है बराबरी। उस बराबरी से एक सीढ़ी नीचे उतरो। आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, राजकीय बराबरी, धार्मिक बराबरी। उससे एक सीढ़ी और नीचे उतरो तो उसके बाद आएगी – समता, पूर्ण समता, संभव समता। तब एक सीढ़ी और नीचे उतरो। तब अधिकतम और न्यूनतम की सीमा लगाओ।'

इसमें डॉ. लोहिया ने धार्मिक बराबरी की भी बात की है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के शब्द नहीं हैं, ये कोई शिवसेना के शब्द नहीं हैं। महान समाजवादी डॉ. लोहिया ने धार्मिक समता, धार्मिक बराबरी की बात क्यों की थी? इसका मतलब यह है कि इस देश में धार्मिक विषमता है, सांस्कृतिक विषमता है और इस तरह सामाजिक–सांस्कृतिक समन्वय की बात करने वाले लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि किस सांस्कृतिक समन्वय की बात करते हो? डॉ. लोहिया ने सांस्कृतिक समन्वय की बात को कहते हुए इस संसद में 26 मार्च, 1966 को बोलते हुए कहा था –

'समन्वय दो तरह का होता है। एक दास का समन्वय, एक स्वामी का समन्वय। पिछले 1000 बरस के इतिहास में हिन्दुस्तान ने स्वामी का समन्वय नहीं सीखा, यह एक दास का समन्वय रहा है। इसलिए भारतवर्ष में जो सांस्कृतिक समन्वय की बात करते हैं, यहाँ दासभाव का समन्वय है, स्वामीभाव का समन्वय नहीं है।

इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अगर समाजवाद की बात करो, समता–समाज की बात करो तो पूर्णता में बात करिए। खंडित में बात करने की कृपा मत करिए। आपका बजट बनता है, आप क्या बजट बनाते हैं, आपके बजट का आधार क्या है? आपका बजट साठ–गाँठ से बनाया गया है, गठबंधन से बनाया गया है। किसके गठबंधन से? राजनीतिक दलों का गठबंधन अलग है, लेकिन आपके बजट का गठबंधन अलग है। वह गठबंधन है अर्थ नीति का।

सत्ता और नौकरशाही का गठबंधन, सत्ता और व्यापार का गठबंधन, सत्ता और भ्रष्टाचार का गठबंधन, सत्ता और बहुराष्ट्रीय कम्पनी का गठबंधन। इस बजट में चारों गठबंधन हैं और इन्हीं चार खूंटों पर इस बजट को बनाया गया है।

मैं पहले आपसे कहना चाहता हूं कि सत्ता और नौकरशाही का गठबंधन कैसे? आपका बजट नौकरशाही उन्मुखी है। आपका बजट नौकरशाहियों के द्वारा नियंत्रित है, संचालित है, प्रबंधित है। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब नौकरशाही के हाथ में रहेगा, इसका छोटा सा उदाहरण है कि कितने नौकरशाह पकड़े गए हैं। सत्ता के गठबंधन में नौकरशाही के संबंध में डॉ लोहिया ने इसी लोक सभा में बोलते हुए कहा था– मैं इस सिद्धांत को उठा रहा हूं कि राजनीति और नौकरशाह का संबंध क्या रहना चाहिए। क्योंकि अगर यह तीन–चार सौ मंत्री अपने नौकरशाहों

का इस्तेमाल करते हैं या तो खुद धन बटोरने के लिए, ज़रा गौर करिएगा, या अपने रिश्तेदारों के लिए धन बटोरने के लिए या अपनी पार्टी के लिए धन बटोरने के लिए और मान लें कि धन न भी बटोरे तो शक्ति का संचय करने के लिए ताकि अपने गुट को मज़बूत बना कर राज्य पर कब्ज़ा कर लो। यह चार चीजें उन्होंने गिनायी हैं। नौकरशाही के साथ इसलिए इनका गठबंधन है। जितने घोटाले की बात हमारे साथियों ने की है, हर घोटाले के पीछे किसका हाथ है? नौकरशाही का हाथ है? जितने राजनैतिक नेता पकड़े गए, उनके नाम आ गए, लेकिन नौकरशाही और बड़े व्यापारी घरानों के कितने लोग पकड़े गए, क्या वह जेल में गए? 2जी स्पैक्ट्रम में घराने का हाथ था या नहीं? ... घराने का हाथ था या नहीं? उनका नाम था या नहीं? क्या ... को गिरफ्तार किया गया? ... और ... को क्या गिरफ्तार किया गया?

एमएलए और एमपी पकड़ में आ जाएं तो उन्हें गिरफ्तार करो, उनके लिए आवाज़ लगाओ, लेकिन इन बड़े घरानों के ऊपर हाथ मत लगाओ, क्योंकि उनकी पूंजी से, उनके पैसे से सरकार चलाते हो। यह है व्यापार और नौकरशाह का गठबंधन। इस गठबंधन पर सरकार को चलाते हो। मैं हिन्दुस्तान के गांव, गरीब, किसान, मजदूर और देश के नौजवानों से कहता हूं कि आओ, बढ़ो, उमंग से उछाल मारो। एक बार हनुमान के जैसे कूद चलो। उस पार जाओ। या तो अन्यायी, अत्याचारी, जुल्मी, जालिम सत्ता को जला कर राख कर दो या समुद्र में डूब कर मर जाओ। लेकिन अब चैन से मत बैठो। सहते–सहते हम थक चुके हैं।

इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आपके बजट का आधार क्या है? मैंने यह चार्ट बनाया है। इसमें पांच चीज हैं– भय, भोग, भ्रष्टाचार, भ्रांति और भगदड़। यही आपके बजट का आधार है। भय क्या है? 12.12.12 को एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है– दिनांक 31.10.12 की स्थिति के अनुसार 57 मामले सुनवायी के लिए सीबीआई के अधीन लम्बित हैं। जिनमें आठ पूर्व मुख्यमंत्री, 71 राजनैतिक दलों के पदाधिकारी, पूर्व संसद सदस्य, पूर्व विधायक, पूर्व पार्षद और विभिन्न दलों के सदस्यों सहित शामिल हैं। इन सुनवायी के अधीन मामले में एक पूर्व मुख्यमंत्री मामलों में शामिल हैं, पदाधिकारी इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि। यही तो है आपका आधार– भय। भय दिखाओ, मेरे साथ आओ, चरण चुम्बन कर लो। मेरे चरण चुम्बन में आओ, सिर झुकाओ, नहीं तो सीबीआई है, इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट है, आयकर विभाग है। घेरेंगे, फंसाएंगे, जेल में बंद कर देंगे और इसके कारण

राजनैतिक दलों का यह चरित्र बन गया है कि सड़क पर रहते हो तो सरकार के खिलाफ बोलते हो, सदन में आते हो और जब सरकार गिराने का मौका आता है तो उनके साथ हाथ मिलाते हो। वाह रे यह दोहरा चरित्र राजनैतिक दल का। क्या इससे हिन्दुस्तान बनेगा? इससे हिन्दुस्तान नहीं बन सकता है। इससे देश नहीं बन सकता है, इसलिए हिन्दुस्तान के उन पिछड़े दलितों और आदिवासियों से मैं कहना चाहूंगा कि इन दोहरे चरित्र वाले को जब तक साफ नहीं करोगे, तब तक हिन्दुस्तान की राजनीति सुधरेगी नहीं, हिन्दुस्तान की व्यवस्था सुधरेगी नहीं। तुम उनके पीछे जाति के नाम पर दौड़ते रहोगे, दलदल में धंसते रहोगे। वह जाति के नाम पर लाएंगे, तुम को कांग्रेस के जंगल में फंसाएंगे। कांग्रेस तुम्हारी हड्डी खा जाएगी, कांग्रेस तुम्हारी मांस–रक्त पी जाएगी। तुम्हारे पूर्वजों का पीया है, तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी।

इसलिए कांग्रेस के साथ–साथ उन दलों को भी सावधान जो कांग्रेस के साथ आंख में आंख मिलाते हैं और कांग्रेस के साथ गले मिलते हैं। बाहर आंख में लाली और अन्दर कांग्रेस की दलाली– – ये दोनों काम एक साथ नहीं चलेगा। इसलिए सभापति महोदय, मैं आप से विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा। मैं अपनी बात को मुख्तसर में कहते चला जा रहा हूं। इस सरकार में अंतर आया है। गांव–शहर का अंतर, कृषि और उद्योग का अंतर, गरीब और अमीर का अंतर, जनता और नौकरशाह के बीच अंतर और खाई बढ़ी है जो निरंतर बढती चली जा रही है। क्या इस बजट से वह खाई कम होगी? क्या इस बजट के द्वारा वह खाई पाटी जाएगी? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। इस का भी कारण है। मैं वह कारण आप को बता देना चाहता हूं। दो–चार मिनट में मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा।

अन्तर कहां–कहां बढ़ा है, जरा गौर करिए। वर्ष 1951 में गांव के लोग थे 82.7, वर्ष 2001 में ये हो गए 72.2 यानि माइनस 10.5। यह आंकड़ा है। गांव के 10.5 प्रतिशत लोग कहां भाग गए, कहां डूब गए? गांव का किसान था। वह एक एकड़, दो एकड़, ढाई एकड़, पांच एकड़ जमीन जोतता था। गांव में खाने के लिए रोटी नहीं, तन पर कपड़ा नहीं, रहने को मउाएान नहीं रहा। वह शहर में भाग आया। शहर में रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, फुटपाथ पर रहता है, पेड़ के नीचे सोता है। ये 10.5 किसानों को आप ने गरीब बनाया है, मज़दूर बनाया है। वर्ष 1951 में किसान 71.9 थे, वर्ष 2004 में उनकी संख्या 54.4 हो गयी। बाकी 17.5 किसान कहां लुप्त हो गए? गया में खेतिहर मज़दूर 28.1 थे, वर्ष 2001 में बढ क़र हो गए 45.6। आप के

आंकड़े बताते हैं कि 17.5 किसान लुप्त हुए हैं और 17.5 खेतिहर मज़दूरों की संख्या बढ़ी है।

मैं आप से प्रार्थना करना चाहूंगा। आप बजट में पांच लाख करोड़ रुपये कर्ज़ लेते हैं और तीन लाख करोड़ रुपये सूद चुकाते हैं। मैं गांव का किसान हूं। पांच लाख रुपये कर्ज़ लिया, तीन लाख रुपये महाजन को सूद दिया, बच गया दो लाख रुपये और बजट बन गया सोलह लाख रुपये का। साहब, आप किस को धोखा देते हैं? मेरे हिसाब से तो वह तीन लाख रुपया सूद में चला गया, बाकी बचा दो लाख करोड़ रुपया। इसलिए यह किस लिए हुआ? केवल सरकारी बैंकों का गैर सरकारी बैंक पर जिन पर एन.पी.ए. का बकाया है, बट्टा खाते का बकाया है, एक करोड़ रुपये से ऊपर जिन पर टैक्स का बकाया है, उन को जोड़ दें तो वर्ष 2009 तक के आंकड़े मेरे पास है। वह 2,90,643 करोड़ रुपये होता है। यह बकाया जो बड़े घरानों के ऊपर है और जिसे आप ने छोड़ा है, अगर यह बकाया नहीं रहता, अगर यह तीन लाख करोड़ रुपये आप उन से वसूल लिए होते तो आप को कर्ज़ क्यों लेना पड़ता? आप उन को छोड़ते जाते हैं। उन पर लुटाते जाते हैं।

पहले गांव में ज़मींदार होते थे। अजय जी, आप हमारे इधर के बारे में जानते हैं। गांव में पहले बाबू साहब ज़मींदार होते थे। वे खेत बेचते थे, दरवाज़े पर मुज़रा करवाते थे। उसी तरह आज यह सरकार एक तरफ लुटाती है। अगर इन बड़े घरानों को दी गयी सारी छूट को निकाल लें तो यह लगभग दस लाख करोड़ रुपये बनते हैं जिससे एक साल के बजट में केवल पांच लाख रुपये की कमी रह जाती है।

महोदय, आप से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इन बातों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं ज्यादा समय न ले कर केवल एक बात कहना चाहूंगा। एक मामला मेरे पास है। मेरे पास का नहीं है, हमारी नेता सुषमा स्वराज जी को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के इम्प्लॉयज एसोसिएशन वाले ने दिया। वे गांव में किसान के, मज़दूर के खेत में, दूरदराज़ देहातों में काम करते हैं। उन के इम्प्लॉयज ने शर्तें रखी थीं कि उन को भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के बराबर सभी सुविधाएं दी जाएं। बाबू प्रणब मुखर्जी जब यहां वित्त मंत्री थे, उन्होंने उन को बुलाया, बैठाया, समझौता किया और उस कागज़ पर उन के भी विभाग का हस्ताक्षर है, मुहर है। लेकिन, आज के वित्त मंत्री कहते हैं कि हम उस को नहीं मानेंगे। क्यों? क्या प्रणब बाबू का किया हुआ सौदा या समझौता किया हुआ आप नहीं मानेंगे? आप को मानना पड़ेगा। मैं अपनी बात

को अंतिम चरण पर ले जाते हुए आप से केवल इतनी प्रार्थना करूंगा।

सभापति महोदय, मैं हिन्दुस्तान के गांव के गरीब किसान, मज़दूर सब को यहां से आह्वान करना चाहता हूं। आज वहां लाखों–करोड़ों की संख्या में लोग संसद की कार्यवाही को देख रहे होंगे। गांव के गरीब किसान, मजदूरों, दलितों, तुम अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानो। जब तक दोस्त और दुश्मन को पहचानने के लिए तुम्हारी दृष्टि नहीं बनेगी, तब तक तुम ऐसे रहोगे। बैंक में, जितनी अंडरटैकिंग्स हैं, वहां एक भी उस समाज का व्यक्ति नहीं है। कहीं इन पिछड़े दलितों को किसी भी ऊंची कुर्सी पर स्थान नहीं, सैक्रेट्री, ज्वाइंट सैक्रेट्री एवं अंडर सैक्रेट्री भी वहां उस समाज का नहीं है। 'राज चलाओ तुम, खून बहाएं हम, राज चलाओ तुम, तेल लाएं हम और नाच नाचो तुम। ये कब तक देश में चलता रहेगा?

इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस अत्याचार, जुल्म को बंद करो। अब मैं दो पंक्तियां सुना कर अपनी बात को समाप्त करूंगा। जो जयप्रकाश जी के आंदोलन के समय में कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में और जयप्रकाश जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में गाते थे। विधान सभा से मैंने इस्तीफा दिया था। मैंने इमर्जेंसी सेल में अपनी हड्डी जलाई थी, 20 किलो खून सूख गया था। तब मैं गाया करता था। 'लाख–लाख झोंपड़ियों में छाई हुई उदासी है, सत्ता सम्पत्त के बंगले में हस्ती पूर्णमासी है, ये सबब न चलने देंगे, हमने कस्में खाई हैं, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लौहा लेने सत्ता से टकराने को, आज देख लें कौन रचाता मौत के संग सगाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। आओ श्रमिक कृषक मजदूरों इंक्लाब का नारा दो, शिक्षक, गुरुजन, बुद्धिजीवियों अनुभव भरा सहारा दो, तब देखें हम ये सत्ता कितनी दर–बदर बोराई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। इसलिए आओ, सब मिल कर छलांग लगाओ, इस जालिम, जुल्मी, गांव विरोधी, किसान विरोधी सत्ता को जला कर राख नहीं करोगे, तब तक हिन्दुस्तान का कल्याण नहीं होगा। इनके मासूम चेहरे पर मत जाओ, आओ हिन्दुस्तान तक को आजाद करो, गांव गरीब किसान, मजदूर को आजाद करो।

■

Budget is words for the poor and deeds for the rich

M. Venkaiah Naidu

I am happy that the Prime Minister has come. We have got all respect for him. But the question is that the person who is responsible for the Budget, the Finance Minister, is absent from the House. Your Ministers are not able to tell us.... Some other ruling party allies are defending him, I don't know why. Please don't try to defend the undefendable acts of the Finance Minister. What are the highlights of the Budget? The number one highlight is, it is very uninspiring and deceptive, and the second is all around disappointment. Every section is very unhappy. Sir, there is a saying in my Party and we explain our stand towards minorities and we say, 'appeasement of none and justice for all.' Now the Finance Minister coined a new thing saying, 'injustice for all, appeasement of none.' That seems to be the motto of this Government. Every section, be it farmers, be it youth, be it women, be it industry or businessmen, nobody is happy with this Budget. We have the responses across the country. The third highlight is, 'broken promises and token allocations.' Another highlight is, 'deficit, deficit and deficit everywhere, no solution anywhere.' That is another

highlight of this Budget. Then one more important highlight of this Budget is, 'words for the poor and deeds for the rich.' That seems to be one of the highlights of this Budget. Sir, take away from the poor and give away to the rich seems to be the policy of the Budget. I am not just saying it for the sake of political criticism. I have got all the figures to back what I am saying. No big and bold steps have been taken. Everybody thought that because of the so-called crisis whatever it is, there will be some big ideas and new steps initiated by this Government. They are all missing. Another surprising thing is that one Government may initiate and another Government after coming to power may change that initiative or may bring in changes. But here in this Government, one Finance Minister proposes something and the other Finance Minister opposes it. Within two years, the same thing happened. What the earlier Finance Minister had said or what he had proposed and what this Finance Minister has disposed, I will give the examples. Sir, another thing is that the people expected the Government through Budget to come to some solution to the major challenges faced by the country. Unfortunately, they are all missing. Another important highlight of this Budget is, 'silent and violent' black money. There is not even a single word in the entire Budget Speech of the Finance Minister about the black money stashed in foreign accounts and the black money that is generated within the country and being used for different purposes.

The last one is that the devil is there in the details. If you go through the Budget, then, you will understand. Someone told me, "Venkaiahji, it is a harmless Budget, because no steps are taken. Why are you worried?" My point is, our country is facing multi-dimensional challenges in every sector. People expected this Government to come with some solutions and then boost the economy, raise the confidence of people and increase the value of rupee. This was the expectation. Create buoyancy in the market, create employment and create confidence among the people. All these things are missing in this Budget. Sir, the Budget has failed

to address two important issues. One is corruption. There is no mention about it. The second is inflation, which is really breaking the backbone of the ordinary people and, particularly, the middle class. Sir, other important aspects are slow growth rate, growing unemployment, agricultural crisis and presence of black money which is stashed abroad. These are the other burning issues. The Finance Minister, unfortunately, could not address any of these challenges. As I told you, there is no mention of fighting corruption in the entire Budget Speech. Today, the country's economy has slowed down to alarming levels, a decade's low. What is needed is a Budget, some glucose, which will boost the economy. That is also missing. Sir, the last Budget returned the country to pre-reforms growth rate of five per cent, unfortunately. This Budget also has the potentiality of carrying forward the same. The other day, the hon. Prime Minister said, let us not demoralise. I do agree with him. But, at the same time, can we be silent on facts? Should we not understand the challenges? Is it not the duty of the Opposition to bring it to the notice of the Government and ask them the responses to that? That is our duty. We are doing it. We will be very happy if the growth rate increases. We will be happy if infrastructure picks up further momentum. We will be more than happy if even the Foreign Institutional Investors (FIIs) also have got more confidence. But, at the same time, it is all your making, this Government's making, that has created this situation. Sir, in every Budget speech, continusouly, the Finance Minister has been saying that they are reducing fiscal deficit, they are taming inflation and they are controlling prices and also about 8 to 9 per cent growth. This has been talked continuously in the last nine years of this Government's tenure. But, what is the result? At the end of it, everybody foregts it and the same thing continues. This is what is happening. Sir, in this Budget, it is not the fear how the fiscal deficit of 4.8 per cent equal to Rs.4,00,000/- crores will be bridged. There are only two ways. One is, print new notes and another is borrow. The first will increase inflation and the second will lead to

insolvency. These are the options you are leaving before the country. Sir, the Railway Minister criticised his predecessor. That has become a fashion in this Government, each Railway Minister criticising his predecessor. Now, the Finance Minister has also criticised his predecessor. He said and I quote: "In the Budget for 2012-13, the estimate of Plan Expenditure was too ambitious and the estimate of non-Plan expenditure was too conservative." There is no continuity in this Government. It is your own Finance Minister. Now, that Finance Minister is occupying the highest post in the country. I don't want to mention his name and I don't want to drag him into controversy also. But it is a fact that this Finance Minister in his Budget Speech disagreed with the outgoing Finance Minister and made that mention. That shows that all is not well within this Government.

Sir, another jugglery created by the Finance Minister is this. He should have compared his Budget Estimates with that of the previous year's Budget Estimates. He did not compare his Budget Estimates with the previous year's Budget Estimates. He compares his Budget Estimates with the Revised Estimates. Then, what is the sanctity of the Budget? This is nothing but deception. Credibility of the Budget system is lost. Sir, in the Central Plan outlay, Budget Estimates for the coming year 2013-14 is Rs. 5,55,322/- crores. Earlier, it was Rs.5,21,025/- crores for the current year. The Revised Estimate for the current year is Rs.4,29,187/- crores. If you compare Revised Estimates of the current year with the Budget Estimates of the next year, you will find that it is up by nearly 30 per cent. If you compare the Budget Estimates of the current year with the next financial year, you will find that the increase is merely Rs.34,297/- crores. That is 6.58 per cent, which is lower than the rate of inflation. This is the point I want to make.

The so-called increase that you have made is lower than the rate of inflation. It is coming to only 6.58 per cent. How do you explain this? There is the same story with regard to education, with regard to health and about other sectors also. In most cases,

the increases in terms of Budget Estimates barely cover the inflation, or, sometimes, it is even less. If you have an increase of 6 per cent or 7 per cent and if there is an inflation of 7 per cent or 10 per cent, then what growth are you going to achieve? This is what I want to highlight. Sir, the gloomy situation is the making of the UPA only. The Economic Survey confirmed the challenges. They include huge deficit, both fiscal and revenue. Earlier our hon. Prime Minister and the Finance Minister were assuring us, 'India will not be affected by the slowdown and our fundamentals are strong.' You yourself said that we are not going to be affected by whatever happening in the international arena. Sir, the Finance Minister, during a Hindustan Times Conclave, said, "India is well insulated from the US financial crisis. There is no cause for alarm." Then, what went wrong? He should explain it. He is not there to explain it, but he should explain. I am speaking for the sake of the country because the Finance Minister is not there. Admitting that there has been a slowdown, the PM, only the other day, said that in another two three years' time, the economy will return to a robust growth of 7-8 per cent. I hope it happens. But, Sir, you have been in power for the last nine years. Now you are asking for two-three more years. What is going to happen? And then you are going to be out within one year. Sir, there have been some domestic factors. It is strange to hear him advising not to dampen the spirit of our people. Who has dampened the spirit? This is the question I want to ask the Government. Sir, after completely denying, many a times, about slowdown, the Government is now using global slowdown as an enemy to curb the failures of this Government. Sir, even the International Monetary Fund said, "India's problems are mostly domestic and largely of its own making." It is not my quotation. It is International Monetary Fund which is saying it. Sir, earlier, the UPA blamed the Left. Now the Left has left. Then what are the right things that you have done to set right the situation? I would like to know it. For five years, you have been blaming the Left and they have left, and now what right things have you done

to set right the situation? This is a question. Four years are over. But you are not able to do anything. Sir, your Economic Survey starts with the following sentence: 'While India's recent slowdown is partly rooted in external causes, domestic causes are also important.' This is your own Economic Survey which is saying it. Sir, mismanagement of economy and policy paralysis have led to the present situation. I am happy that the hon. Prime Minister is here. Even a soft-spoken and noted industrialist, Shri Kumar Mangalam Birla, openly complained of the country's inconsistency and lack of transparency in business policies. He said, 'we are in 36 countries around the world; we haven't seen such uncertainty and lack of transparency in policy anywhere.' He is an old businessman. I am talking from the angle of the businessmen. They are also equal partners in the growth story of this country. I am not among those people who criticize business, who criticize industry, who condemn them and later go to them. That is a different matter. But, Sir, my point is that this is the agony felt by many industrialists, and this man never speaks. He does not criticize others also. He has spoken out of agony. I just wanted to bring it to the notice of the Government. Sir, let me point out that even in the face of adverse external environment, 48 countries grew faster than India; 48 countries. In the year 2012, 27 countries grew faster than 7 per cent, 10 grew faster than 9 per cent. If those countries can grow faster than 9 per cent, faster than 7 per cent, what prevented India to march forward? That is the question. Nobody is able to understand this. All that is required is : prudent economic management, good governance and revival of domestic policies. Sir, may I remind you that the growth target for the present year was 7.6 per cent, but the achievement is only 5 per cent? Even you could not reach your own Mid Year Review target of 5.7-5.9 per cent. In the current year, the CSO estimates the growth at 5 per cent, while the RBI is saying, it is 5.5 per cent. Going by your own governance and performance records, it is hard to achieve the projected growth rate of 6.1 to 6.7 per cent in the

next fiscal.

That is the worry. Morgan Stanley and HSBC have downgraded India's growth rate to six per cent, for 2013-14. It is their assessment. Earlier, their estimate was 6.2 per cent. Now, they have said, it would be only six per cent. So, there is no clear roadmap to achieve the targeted nine per cent or eight per cent growth rate. Even the Planning Commission says that it is not easy to achieve eight per cent growth rate in the 12th Plan. This has been said by the Planning Commission. It is not my charge. Sir, this was disclosed in a covering paper by the Planning Commission. Unless they go in aggressively for investment in human resources and manufacturing sector, they would not be able to achieve even eight per cent growth rate in the 12th Plan. This is the worry. I do not know how the Government is going to tackle the situation. Sir, I now come to another point. In 2004, when we had left office and they came into power, at that time, the economy was growing at 8.1% to 8.4%, which has been the fastest in fourteen years. It was the last year of our regime. In 2012-13, growth rate fell to five per cent. From 8.1 per cent to 8.4 per cent, they brought it down to five per cent. They assumed office in 2004. The Economic Survey of 2004 says, and I quote, "The economy appears to be in resilient mode in terms of growth, inflation and balance of payments, a combination that offers large scope for consolidation of the growth momentum with continued macroeconomic stability." It further says, "The economy has enjoyed the benefits of relatively low inflation with comfortable stocks of food grains, enhanced competition in the market and an appropriate mix of fiscal and monetary policies." It further said, "The double-digit annual average inflation rate of 10 per cent between 1991-92 and 1995-96 has come down to 4.2 per cent, between 2001 and 2004, the last three years of NDA rule." This is what has been stated in the Economic Survey during the first year of their Government. Sir, even the present Finance Minister, hon. Shri Chidambaram, while presenting the first Budget of the

UPA in 2004, himself accepted, "The economic fundamentals appear strong and balance of payment is robust." From 'robust', they have now brought it to a roast! So, those were the words of Mr. Chidambaram. He is an expert in the English language and he knows what he says.

Sir, who has brought the nation's economy to such a pass? This is what I want to ask, and I know that they have no answer.The NDA started with a four per cent growth rate and reached 8.1 to 8.4 per cent. They started with eight per cent and now they have brought it down to five per cent. This has been their achievement through all their Budgets. Sir, good policy decisions in the year 2000 by NDA were responsible for a higher growth rate. I would like to stress one more point here. Even the initial high growth rate under the UPA Government was because of the good foundations laid down by Shri Atal Bihari Vajpayee and his Government. This Government enjoyed those fruits for the initial three-four years. Subsequently, they have ruined it and now, that is the situation prevailing in the country. Firm foundations were laid down by the BJP-led NDA Government. We had taken so many important decisions during our regime such as the first of its kind, well-executed, Golden Quadrilateral Project, powering the Electricity Act, and so on. Dr. Manmohan Singh had initiated the reforms, but the reforms were actually implemented by the Shri Atal Bihari Vajpayee-led NDA Government, which has become a turning point in India's history. Their Government of today is not able to take any initiative. The other important issue is inflation. The UPA Government has given the aam aadmi the biggest gift of inflation and rising prices. It was targeted to be around 6.5 per cent, but it remained above seven per cent for most part of the year. Food inflation went up to 10.79 per cent in January and remained above 10 per cent. As per records, for the last month, it was 10.91 per cent, as against 8.3 per cent in the previous year. This Budget has, yet again, failed to bring back smiles on the face of the Indian home-makers. Today, it has become almost impossible for a

housewife to run the house. The price of every item is sky-rocketing. Be it electricity, water, gas, diesel, petrol, pulses, wheat, sugar or rice, the price of every commodity is only going up and further up. This is the biggest achievement of this Government — making the life of the common people miserable. They have reduced the limit for LPG cylinders.

It was available on demand to everybody. What happened to you? You brought it down to six.

With a heavy heart and with a lot of agony, I am laying my speech on the Table of the House. This has never happened. We are setting a very bad precedent. I don't want to question the decision. At the same time, the Budget of India is an important document. Where the Parliament should discuss it threadbare, who is responsible for this, the Government should explain. It is the Government's failure to manage the situation that has resulted in this situation. Secondly, Sir, the deficit is a major challenge before the country, the fiscal deficit, revenue deficit, current account deficit, and, above all, trust deficit. The situation today has arisen because there is a trust deficit in this Government. I am not holding the Finance Minister responsible for this trust debate. When I say trust deficit, trust deficit is because of the mishandling. You do not know how to run a Government. You do not consult your allies. You always try to insult them.

I am not going into the details. Sir, today when I woke up in the morning, astonishingly there was a news that some people were raided by the CBI. That party has withdrawn support yesterday and you misuse CBI. And today the Home Minister says that it is inquired into, and they have been ordered to stop it and explain in 60 minutes. You say that you have no jurisdiction on the CBI. Then, how can you give such instructions? That is nothing but blackmail. You are trying to misuse CBI. We protest against this. This is against democracy. My point is, the Finance Minister should incorporate the response to all the points, raised by various Members, during his speech on the Appropriation Bill

because at least we must have an opportunity then to understand what is the thinking and what are the actions proposed by the Government or taken by the Government. Today, I request the Finance Minister to please go through the economic newspapers of today, "The Headlines Today", the Captains of Industry and know what is their feeling and try to understand that. The prices of essential commodities are rising, unemployment is growing, corruption is also increasing and the Government is silent on all these issues. So, I would like the Government to respond to all these issues. As per your direction, I am laying my speech on the Table of the House by signing every page.

■